नई दिल्ली । बुधवार , 22 अप्रैल, 2026
बैशाख कृष्ण पक्ष नवमी, सिद्धार्थि संवत्सर विक्रम संवत 2083
वर्ष :12, अंक :106 / मूल्य 3.00 रुपए । पृष्ठ 12

दैनिक
विश्व केसरी
नई दिल्ली संस्करण
सिर्फ पत्रकारिता...
vishwakesari.com
@vishwakesariTV
@vishwakesari
vishwakesari
आर. एन. आई. संख्या डीईएलएच आईएन/2015/61415

@ खेल फ्रेंच ओपन से पहले पूरी तरह फिट होना है...
@ विचार साइबर अपराध का बदलता चेहरा...
@ व्यापार भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ हरे निशान में बंद...

संक्षिप्त खबर

शानदार समझौते के साथ होगा अंत - ट्रंप

वॉशिंगटन। दुनिया भर की निगाहें इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मंडरा रहे युद्ध के बादलों पर टिकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तनावपूर्ण माहौल में अपनी स्थिति साफ कर दी है कि शांति की समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि 22 अप्रैल की आधी रात के बाद वह किसी भी कीमत पर संघर्षविराम को आगे नहीं बढ़ाएंगे।

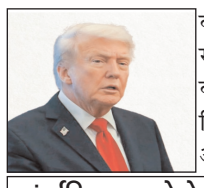

संघर्षविराम बढ़ाने से किया इनकार

क्या बुधवार के बाद अमेरिका फिर से शुरू करेगा बमबारी ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कूटनीति के लिए अब और समय देना मुमकिन नहीं है।

यूपी: 69000 शिक्षक अभ्यर्थी आर-पार की लड़ाई के मूड में, आंदोलन आज

अलर्ट मोड पर आया प्रशासन; कई हुए हाउस अरेस्ट

एजेंसी ■ लखनऊ

69000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का बुधवर को राजधानी लखनऊ में बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है। इसमें अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी शामिल होंगे। हालांकि आंदोलन की घोषणा को देखते हुए पुलिस-प्रशासन भी सतर्क है। जिलों में अभ्यर्थियों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है।

इस भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस प्रकरण पर सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। इससे मामला लटकता जा रहा। इस प्रकरण की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2024 में हुई थी। उसके बाद से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता, सुशील कश्यप ने कहा कि सरकार की ओर से कोई पहल न करने से मामला लटकता जा रहा है।

ऐसे में हम सभी 22 अप्रैल को लखनऊ में बड़ा धरना-प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद सरकार ने 6800 अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की लेकिन नियुक्ति नहीं दी।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले छह वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर आदि जिलों में युवाओं का नेतृत्व करने वाले अभ्यर्थियों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। फिर भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन होगा।

पश्चिम बंगाल-तमिलनाडु में थमा चुनाव प्रचार, कल होगा मतदान

एजेंसी ■ नई दिल्ली

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से 48 घंटे पहले मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के लिए मतदान होने हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

चुनाव प्रचार थमने से पहले दोनों राज्यों में शीर्ष नेताओं और उम्मीदवारों ने समर्थकों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं, चुनाव प्रचार थमने के बाद अब कोई भी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा या रैली नहीं कर सकेगा।

पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो यहां इस बार दो चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाना है। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होना है।

इस चरण में कुल 1,478 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं, तीन करोड़ 60 लाख 77 हजार 171 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन मतदाताओं में एक करोड़ 75 लाख 77 हजार 210 महिलाएं अपने मत का इस्तेमाल करेंगी। आरक्षण को लेकर बने माहौल के बीच इस बार पश्चिम बंगाल में महिलाओं की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है।बंगाल में पहले चरण में जहां मतदान होने हैं, उनमें उत्तर बंगाल के आठ, दक्षिण बंगाल के तीन व जंगलमहल अंचल के पांच जिले शामिल हैं।इनमें मुर्शिदाबाद की 22, कूचबिहार की 9, जलपाईगुड़ी की 7, अलीपुरद्वार की 5, कलिंपोंग की एक, दार्जिलिंग की 5, उत्तर दिनाजपुर की 9, दक्षिण दिनाजपुर की 6, मालदा की 12, बीरभूम की 11, पश्चिम बर्द्धमान की 9, पूर्व मेदिनीपुर की 16, पश्चिम मेदिनीपुर की 15, झारग्राम की 4, पुरुलिया की 9 और बांकुड़ा की 12 सीटें शामिल हैं।

दिल्ली में एफसीआई के जरिए फिर शुरू होगी गेहूं खरीद

एजेंसी ■ नई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किसानों के हित में एक अहम पहल की है। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के जरिए गेहूं की सरकारी खरीद फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिल सकेगा और स्थानीय कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

सीएम रेखा गुप्ता ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों के कल्याण और उनकी आय को सुरक्षित करने के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है और यह फैसला उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से दिल्ली के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा और वे अधिक सशक्त बनेंगे।

इस विषय पर उन्होंने हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखकर रबी विपणन सत्र में दिल्ली में एफसीआई के जरिए गेहूं खरीद तत्काल बहाल करने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था ।

केरल के त्रिशूर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 13 की मौत

एजेंसी ■ त्रिशूर

केरल के त्रिशूर जिले के मुंडथिक्कोडु इलाके में मंगलवार को एक पटाखा निर्माण यूनिट में भीषण विस्फोट गया। इस विस्फोट में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब शहर में आयोजित होने वाले वार्षिक हिंदू मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम की तैयारियां चल रही थीं।

घटनास्थल पर पहुंचे राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट के समय यूनिट में करीब 40 लोग काम कर रहे थे, क्योंकि आयोजकों द्वारा कर्मचारियों के लिए दोपहर का भोजन लाया गया था।

अधिकारी ने कहा, 'हमें सूचना मिली है कि सात लोग वहां से भागने में सफल रहे।

बताया जा रहा है कि यह विस्फोट उस पटाखा इकाई में हुआ, जहां त्रिशूर पूरम के थिरुवंबाडी गुट के लिए आतिशबाजी के सैंपल तैयार किए जा रहे थे।

सूत्रों के मुताबिक, घटनास्थल

पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, जिसमें आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। प्रारंभिक जानकारी में लगभग 40 लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी, जिनमें से कम से कम आठ की हालत गंभीर बताई गई थी।

घटना के तुरंत बाद एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और प्रशासन ने त्रिशूर मेडिकल कॉलेज सहित आसपास के अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए, ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके।

विस्फोट के बाद इलाके में घना धुआं और आग फैल गई, जिससे बचाव कार्यों में भी कठिनाई आई। घटनास्थल पर मौजूद अधजले और बिना फटे विस्फोटकों के कारण राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हुआ। पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गईं।

विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिससे धमाके की तीव्रता और वहां मौजूद विस्फोटक सामग्री के पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है।

राज्य संचालित केआईएलए के कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने तेज धमाके की आवाज सुनी और पहले उन्हें लगा कि यह भूकंप है।

एक अधिकारी ने बताया, 'बाद में जब हम चाय के लिए बाहर आए, तब हमें पता चला कि यह विस्फोट था। यह हादसा त्रिशूर पूरम की तैयारियों के चरम के दौरान हुआ है, जब एक दिन पहले ही ध्वजारोहण के साथ उत्सव की औपचारिक शुरुआत हुई थी। फिलहाल विस्फोट के सटीक कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन जांच में पटाखा सामग्री के भंडारण और हैंडलिंग में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की आशंका पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है और कुछ समय के लिए जनजीवन भी प्रभावित हुआ है।

एनसीआर में गर्मी के साथ जहरीली हवा का डबल अटैक

24 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी

एजेंसी ■ नई दिल्ली

एनसीआर के लोगों के लिए मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। जहां मार्च में फरवरी जैसी हल्की ठंडक का एहसास हुआ था, वहीं अब अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ही मई-जून जैसी भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनने लगी है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक लगातार हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 21 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि 22 और 23 अप्रैल को तापमान बढ़कर 43 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है।

24 अप्रैल को भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। इन दिनों दोपहर और शाम दोनों समय हीट वेव की स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी गई है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है।

हालांकि 25 और 26 अप्रैल को मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। इन दिनों अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके बावजूद गर्मी से राहत सीमित ही रहने की उम्मीद है।

गर्मी के साथ-साथ वायु गुणवत्ता भी लोगों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन रही है।

सीएम ममता के गुंडों को पाताल से भी ढूंढ कर सलाखों के पीछे भेजेंगे: अमित शाह

एजेंसी ■ चांदीपुर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के चांदीपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पहले चरण की आखिरी सभा है, और मैं आज चांदीपुर से दीदी को कहने आया हूं—दीदी, टाटा, बाय-बाय... अब आपका समय समाप्त हो गया है। आपने बंगाल की जनता को बहुत परेशान कर लिया। अब आपकी जाने की बारी है और कमल खिलने की बारी है।

अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव के पहले चरण की आखिरी रैली है। मैं चांदीपुर की दीदी से कहना चाहता हूं, 'टाटा, अलविदा। आपका समय समाप्त हो गया है! आपने बंगाल की जनता को बहुत परेशान किया है। अब आपके जाने का और भाजपा के प्रवेश का समय आ गया है।' आज मैं घुसपैठियों को कहकर जाता हूं कि 4

तारीख को काउंटिंग है और 5 तारीख को भाजपा की सरकार बनेगी। जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो। अब बंगाल में भय से भरोसे की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू होगी।

उन्होंने कहा कि आज मैं कहकर जाता हूं कि यहीं चांदीपुर और आसपास के क्षेत्रों में पान की खेती होती है, इसलिए एक बड़ा पान का अनुसंधान रिसर्च सेंटर भारत सरकार चांदीपुर में बनाने का काम करेगी।

मैं आज ममता के गुंडों को भी कहकर जाता हूं कि 23 तारीख को घर के बाहर नहीं निकलना। 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। पाताल से भी ढूंढ कर सलाखों के पीछे भेजेंगे।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराया है, और आज मैं कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम करेगी।

बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ थीं। हालांकि, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। जब कांग्रेस ममता बनर्जी के समर्थन से सत्ता में थी, तब वे आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। उरी में आतंकवादियों ने हमला किया और सर्जिकल स्ट्राइक की गई।

पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, कांग्रेस ने ओम बिरला को लिखा पत्र

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन दिया है।

अपने पत्र में वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने 18 अप्रैल 2026 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोकसभा के सदस्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उनके इरादों पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि यह संसद की गरिमा और सांसदों के अधिकारों का उल्लंघन है।

चुनाव आयोग पहुंची भाजपा: कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

खरगे के बयान पर गरमाई सियासत

एजेंसी ■ कोलकाता

देश के चुनावी माहौल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए हालिया बयान ने एक नया राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है। दरअसल तमिलनाडु में एक रैली को दौरान उन्होंने पीएम की तुलनी आतंकवादी से कर दी थी। भाजपा ने इस बयान को न केवल अपमानजनक बताया है, बल्कि इसे चुनावी आचार संहिता का सीधा उल्लंघन करार दिया है।

भाजपा की ओर से चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी ने यह साफ कर दिया है कि वे इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष को घेरने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। भाजपा ने इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री पद की गरिमा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता से जोड़ दिया है।

क्या भाजपा ने चुनाव आयोग से क्या मांग की ?

भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को एक औपचारिक पत्र लिखकर मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर तत्काल संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। भाजपा का तर्क है कि खरगे का बयान प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग खरगे को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने या अपना बयान वापस लेने का निर्देश दे।

इसके साथ ही, भाजपा ने आयोग से यह भी अपील की है कि कानून और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार खरगे पर चुनावी अभियान से जुड़े उचित प्रतिबंध लगाए जाएं या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि चुनावी मर्यादा बनी रहे।

कठोर कानूनी कार्रवाई की भी मांग

भाजपा केवल चुनावी प्रतिबंधों तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि उसने खरगे के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। आयोग को भेजे गए पत्र में भाजपा ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं का जिक्र किया है।

भारत को 100 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन का लक्ष्य रखना चाहिएः नितिन गडकरी

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि भारत को जल्द ही ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में 100 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि आयातित तेल पर निर्भरता कम हो सके, जो ईरान युद्ध जैसे भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के प्रति देश को संवेदनशील बनाता है।

मंत्री ने बताया कि भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 87 प्रतिशत आयात करता है।

केंद्रीय मंत्री ने इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉन्क्लेव में अपने संबोधन में कहा, 'हम 22 लाख करोड़ रुपए के फॉसिल फ्यूल आयात करते हैं, जो प्रदूषण भी बढ़ाता है। इसलिए हमें वैकल्पिक ईंधन और बायो-फ्यूल के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'निकट भविष्य में भारत को 100 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण आज ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना जरूरी है।'

2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई20) लॉन्च किया था। वर्तमान में भारतीय वाहन ई20 पेट्रोल पर थोड़े बदलाव के साथ चल सकते हैं, जिससे इंजन में जंग जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। ब्राजील जैसे देशों में 100 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का उपयोग होता है।

पेट्रोल और डीजल वाहनों के उपयोग को कम करने की जरूरत पर जोर देते हुए गडकरी ने कहा, 'हम लोगों को जबरदस्ती पेट्रोल-डीजल वाहन खरीदने से नहीं रोक सकते। ई20 को लेकर सोशल मीडिया पर बढ़ती चिंताओं के बारे में उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम सेक्टर इस कदम के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है।

उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनियों से कहा कि वे लागत के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान दें, इससे उन्हें नए बाजारों में जगह बनाने में मदद मिलेगी।

गडकरी ने यह भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, लेकिन इसे व्यावहारिक बनाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशनों की लागत कम करना जरूरी है।

उन्होंने आगे कहा, 'हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्ट में दिक्कत है। साथ ही, हमें 1 किलो हाइड्रोजन को 1 डॉलर में तैयार करना होगा ताकि भारत ऊर्जा निर्यातक बन सके।

' उन्होंने कचरे से हाइड्रोजन बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

मंत्री ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान देकर भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

देश में दूध की आपूर्ति सामान्य, डेयरी प्लांट्स को पहले के मुकाबले 70 प्रतिशत तक एलपीजी सप्लाई जारी: सरकार

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश में दूध की खरीद, प्रोसेसिंग और सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। सरकार ने नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित इंटर-मिनिस्ट्री ब्रीफिंग के दौरान बताया कि डेयरी सेक्टर पर किसी तरह का नकारात्मक असर नहीं पड़ा है और बाजार में दूध व डेयरी उत्पादों की उपलब्धता स्थिर है।

बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जानकारी दी कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर कई अहम कदम उठाए गए हैं, ताकि डेयरी सप्लाई चेन में कोई बाधा न आए। सरकार ने यह भी बताया कि इस पूरे संकट के दौरान दूध उत्पादकों को भुगतान भी लगातार जारी रहा है, जिससे किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई।सरकार के अनुसार, डेयरी सेक्टर की स्थिति की समीक्षा के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 8 अप्रैल 2026 के आदेश के तहत डेयरी प्लांट्स को पहले के मुकाबले 70 प्रतिशत तक एलपीजी सप्लाई जारी रखने का फैसला लिया गया, ताकि उत्पादन प्रभावित न हो। साथ ही, जहां संभव हो वहां एलपीजी की जगह पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) के उपयोग को बढ़ावा देने की सलाह भी दी गई है।

पैकेजिंग सामग्री की सप्लाई को लेकर भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। पेट्रोकेमिकल जॉइंट वर्किंग ग्रुप के जरिए डेयरी सेक्टर के लिए जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए जरूरी एलडीपीई (एलडीपीई) की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, साथ ही पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टाइरीन जैसी सामग्रियों की सप्लाई भी जारी रखने का आश्वासन दिया गया है।

मध्य पूर्व संकट के बीच एलपीजी आपूर्ति नियंत्रण में, मजदूरों के लिए बढ़ाई गई 5 किलो सिलेंडर की सप्लाईः सरकार

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह नियंत्रण में है और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि देश भर में कहीं भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर गैस खत्म होने (ड्राय आउट) की कोई रिपोर्ट नहीं है। ऑनलाइन गैस बुकिंग बढ़कर करीब 98 प्रतिशत तक पहुंच गई है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) के जरिए करीब 92 प्रतिशत डिलीवरी की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है।

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। उपभोक्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एलपीजी बुकिंग करने और वैकल्पिक ईंधन जैसे पीएनजी, इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही, ऊर्जा बचाने की भी सलाह दी गई है।

बयान में कहा गया है कि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की 100 प्रतिशत सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। कमर्शियल एलपीजी में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य जरूरी सेक्टर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा, प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो सिलेंडर की सप्लाई भी बढ़ाई गई है।

रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाने, बुकिंग अंतराल बढ़ाने और वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। कोयला मंत्रालय ने भी राज्यों को अतिरिक्त कोयला उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए देश भर में लगातार कार्रवाई जारी है। हाल ही में एक दिन में 2200 से ज्यादा छापे मारे गए। पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 274 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर जुर्माना लगाया है और 67 डिस्ट्रीब्यूटर्स को निलंबित किया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि मार्च 2026 से अब तक 5.01 लाख से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं और 5.68 लाख से अधिक नए उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। करीब 39,400 उपभोक्ताओं ने एलपीजी कनेक्शन छोड़कर पीएनजी को अपनाया है, जिससे एलपीजी पर दबाव कम हुआ है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, देश के सभी बंदरगाह सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और कहीं भी जाम की स्थिति नहीं है। 28 फरवरी 2026 से अब तक 9 एलपीजी जहाज और 1 कच्चे तेल का जहाज सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर चुके हैं।

सनातन धर्म आज पूरी दुनिया को सही दिशा दिखा रहा है : डॉ. मोहन भागवत

अगरतला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने मंगलवार पश्चिम त्रिपुरा जिले के मोहनपुर उपखंड के फकीरमुरा गांव में मां सौंदर्य चिन्मयी मंदिर का भव्य उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम आदि शंकराचार्य जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित हुआ। उद्घाटन के साथ ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और कुंभाभिषेक भी संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. मोहन भागवत ने चिन्मय हरिहर विद्यालय की सराहना की, जहां पूरी तरह निशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि शक्ति के साथ-साथ भक्ति भी जरूरी है। केवल सत्य को जानना ही काफी नहीं है, उस सत्य को स्थापित करने के लिए शक्ति की भी आवश्यकता होती है।

अपने संबोधन में सरसंघचालक ने कहा, ''ज्ञान का अर्थ केवल बोलना नहीं है, ज्ञान का अर्थ है समझना। उन्होंने दो हजार वर्षों की यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि दुनिया ने विज्ञान, समाजवाद, राजतंत्र आदि कई प्रयोग किए, लेकिन अब यह महसूस हो रहा है कि दुनिया को भारत के जीवन दृष्टिकोण की जरूरत है। सनातन धर्म आज पूरी दुनिया को सही दिशा दिखा रहा है।

डॉ. भागवत ने जोर देकर कहा कि मंदिर भारतीय सामाजिक जीवन के केंद्र रहे हैं। भारतीय संस्कृति की खासियत यह है कि यहां शक्ति और भक्ति दोनों साथ-साथ चलती हैं। समाज उन लोगों को याद रखता है, जो सबके साथ घुल-मिलकर सेवा का भाव रखते हैं। उन्होंने दक्षिण भारत के चार राज्यों की विशेष प्रशंसा की, जहां सेवा कार्यों में सबसे ज्यादा सक्रियता देखी जाती है। सरसंघचालक ने कहा, ''हमारे यहां कई युगों से विविधता रही है, लेकिन हम एक हैं। विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।'' उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के उत्थान को रोकने के लिए बाहरी ताकतें हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए सभी को सावधान रहना चाहिए और एकता बनाए रखनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, 'आज के युग में केवल सत्य जानना पर्याप्त नहीं है। उस सत्य को स्थापित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। भारत की असली शक्ति उसकी संस्कृति में निहित है। भारत ने कभी आक्रामक मानसिकता नहीं अपनाई। हमेशा शांति और भाईचारे की वकालत की है। आज युद्ध-ग्रस्त दुनिया को ठीक इसी शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है, और भारत इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है।

भारत की पश्चिम एशिया हालात पर पूरी नजर, पीएम के निर्देशानुसार खाड़ी देशों से संवाद जारी : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि भारत की पश्चिम एशिया के बदलते हालात पर पैनी नजर है और उस क्षेत्र के सभी देशों से संवाद जारी है।

पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है और ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों और भारतीय जहाजों की सकुशल निकासी को लेकर बातचीत जारी रखे हुए है।

उन्होंने कहा, 'भारत पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर खाड़ी देशों के साथ संपर्क और संवाद को और मजबूत किया गया है।

जायसवाल ने अहम दौरों का उल्लेख करते हुए आगे कहा, 'हाल के दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सऊदी अरब का दौरा किया, विदेश मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की, और पेट्रोलियम मंत्री कतर गए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भी खाड़ी देशों के अपने समकक्षों के साथ कई बैठक की। इन समन्वित प्रयासों का उद्देश्य भारत और खाड़ी देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय प्रवासियों के कल्याण और अन्य साझा मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने रविवार को रियाद का आधिकारिक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सऊदी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई उच्च-स्तरीय बैठकें कीं, जिनका मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, ऊर्जा सहयोग बढ़ाना और क्षेत्र के अहम घटनाक्रमों पर चर्चा करना था। यह दौरा बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करता है।

अपने दौरे के दौरान, एनएसए डोभाल ने सऊदी के कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात की, जिनमें ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान, विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसाद अल-ऐबान शामिल थे।

जायसवाल से जब पूछा गया कि क्या ईरान ने शनिवार को हुई गोलीबारी की घटना के बारे में भारत को कोई नई जानकारी दी है, तो उन्होंने कहा, 'मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि हम होर्मुज जलडमरूमध्य से अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ईरानी अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। साथ ही, ईरान में हमारे कई भारतीय नागरिक भी मौजूद हैं, इसलिए हम उनकी सुरक्षा और कुशलता को लेकर भी ईरानी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं।

रक्षा क्षेत्र में सरकार का बड़ा कदम, टीआरएडब्ल्यूएल असेंबली सौदे से सेना की ऑपरेशनल क्षमता होगी और मजबूत

नई दिल्ली। भारतीय सेना की माइनफील्ड (बारूदी सुरंग क्षेत्र) भेदने की क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) और इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ करीब 975 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, टी-72 और टी-90 टैंकों के लिए टीआरएडब्ल्यूएल असेंबली एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इससे भारतीय सेना की बारूदी सुरंगों को भेदने की क्षमता में बड़ा सुधार होगा।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस उपकरण की मदद से बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्रों में सुरक्षित रास्ते बनाए जा सकेंगे, खासकर उन सुरंगों में जिनमें एंटी-टैंक माइन और मैग्नेटिक फ्यूज लगे होते हैं। इससे भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमता और मजबूत होगी।

यह समझौता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में किया गया। यह खरीद भारत के रक्षा ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे स्वदेशी उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी। यह 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

बयान में कहा गया है कि इस परियोजना से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और इससे सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

इस बीच, पिछले महीने रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना के लिए दो आधुनिक माउंटेन रडार खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ एक बड़ा समझौता किया था।

करीब 1,950 करोड़ रुपए का यह सौदा देश में रक्षा निर्माण को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते पर नई दिल्ली में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए थे।31 मार्च को जारी मंत्रालय के बयान के अनुसार, 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ दो माउंटेन रडार, उनसे जुड़े उपकरण और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद के लिए लगभग 1,950 करोड़ रुपए का समझौता किया है।

गौतमबुद्धनगरः मानकों के उल्लंघन पर आठ स्विमिंग पूल और जिम बंद, जांच अभियान जारी

गौतमबुद्धनगर। स्विमिंग पूल (तरणताल) और जिमों के संचालन को सुरक्षित एवं मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए जनपद में प्रशासन द्वारा व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 30 जिम और तरणतालों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिसमें कई स्थानों पर गंभीर खामियां सामने आई हैं।

तरणताल/जिम तकनीकी समिति के अध्यक्ष एवं डिप्टी कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान 8 स्थानों पर स्विमिंग पूल और जिमों में आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया गया। इसके चलते संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर दिया गया है और अग्रिम आदेशों तक इन सभी संस्थानों का संचालन बंद करवा दिया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक संचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक उन्हें दोबारा संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि स्विमिंग पूल के संचालन के लिए कई सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। इनमें कोड ऑफ सेफ्टी प्रमाण पत्र, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, सीसीटीवी कैमरे, प्रशिक्षित लाइफगार्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, अग्निशमन प्रमाण पत्र, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट और पानी की पीएच जांच रिपोर्ट जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, पूल परिसर में गहराई के संकेत, खुरदुरी टाइल्स, आगंतुक रजिस्टर तथा नजदीकी अस्पताल और थाना के संपर्क नंबर भी प्रदर्शित होना जरूरी है। वहीं, जिम संचालन के लिए भी कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिम में सीसीटीवी कैमरे, प्रशिक्षित ट्रेनर, अग्निशमन प्रमाण पत्र, अलग-अलग चेंजिंग रूम, मशीनों की सूची, ऑक्सीजन सिलेंडर और आपातकालीन सुविधाएं अनिवार्य हैं। साथ ही जिम में किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट या दवाइयों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे और किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य जनसुरक्षा सुनिश्चित करना और फिटनेस केंद्रों में सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

राशन के लिए धूप में लाइन खत्म, नया टाइमिंग लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी राशन दुकानों के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। अब हितग्राहियों को राहत देने के लिए खाद्यान्न वितरण सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। नए आदेश के अनुसार दोपहर की तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए राशन दुकानें दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बंद रहेंगी। इसके अलावा निर्धारित छुट्टियों के दिनों में दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। पहले राशन दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित हो रही थीं, जिससे तेज धूप में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। समय में बदलाव से अब लोगों को सुबह और शाम के अपेक्षाकृत ठंडे समय में राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले से खासतौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने सभी उचित मूल्य दुकानों को नए समय का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर में अब नहीं होगी पार्किंग की परेशानी! शुरू हुआ हाईटेक सिस्टम

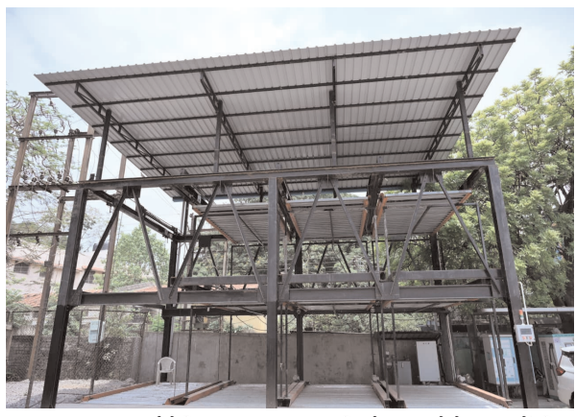

रायपुर। शहर में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हुए रायपुर नगर पालिक निगम ने एक नई पहल की है। नगर निगम मुख्यालय परिसर में अब हाईड्रोलिक पजल कार पार्किंग सिस्टम स्थापित कर दिया गया है, जो सफल परीक्षण के बाद नियमित उपयोग के लिए शुरू हो गया है।

कम जगह में अधिक वाहनों की पार्किंग संभव होगी

पार्किंग की समस्या में कमी आएगी समय और स्थान दोनों की बचत होगी यह सिस्टम खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में बढ़ती वाहन संख्या को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

रायपुर नगर निगम मुख्यालय में हाईड्रोलिक पजल कार पार्किंग सिस्टम शुरू

रायपुर नगर निगम मुख्यालय में

शुरू हुआ यह हाईड्रोलिक पजल कार पार्किंग सिस्टम शहरवासियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगा और पार्किंग से जुड़ी समस्याओं को काफी हद तक कम करेगा।

15वें वित्त आयोग के तहत हुआ निर्माण यह प्रोजेक्ट 15वें वित्त आयोग के तहत पूरा किया गया है। पार्किंग सिस्टम की स्थापना 16 फरवरी 2026 को पूर्ण हुई। इसके बाद आवश्यक बिजली कनेक्शन और तकनीकी परीक्षण किए गए सभी परीक्षण सफल रहने के बाद अब इसे आम उपयोग के लिए शुरू कर दिया गया है।

कैसे काम करता है यह सिस्टम ?

हाईड्रोलिक पजल पार्किंग सिस्टम में—वाहनों को मल्टी-लेयर प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाता है। हाइड्रोलिक तकनीक के माध्यम से गाड़ियां ऊपर-नीचे होती हैं। इससे सीमित स्थान में अधिक वाहन व्यवस्थित रूप से पार्क किए जा सकते हैं

स्मार्ट सिटी की दिशा में कदम

यह पहल शहर को स्मार्ट और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नगर निगम द्वारा भविष्य में भी ऐसी आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है।

बीरगांव में ईंट भट्टी पर छापा तीन बच्चियों का रेस्क्यू

रायपुर। बीरगांव स्थित ईंट भट्टे से सुबह लगभग 6 बजे तीन नाबालिग बच्चियों को मुक्त कराया गया। सभी बच्चियां 14 वर्ष से कम आयु की पाई गई। तीनों बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस प्रकरण में ईंट भट्ठा मालिक पर बाल श्रम निषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा रही । इस कार्यवाही में जिला बाल संरक्षण इकाई से माधुरी शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी संजय निराला, सामाजिक कार्यकर्ता गोरखनाथ पटेल, श्रम निरीक्षक पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता अभिमन्यु भरिया एवं विपिन ठाकुर राज्य समन्वयक एसोसिएशन फॉर वॉलंटियरी एक्शन एवं चाइल्डलाइन टीम के सदस्य शामिल रहे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ वर्णिका शर्मा ने स्पष्ट किया है कि बाल श्रम के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी सतत रूप से जारी रहेगी।

शहरों में बेतरतीब निर्माण, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती से लगाएं रोक : उप मुख्यमंत्री

रायपुर। प्रदेशभर के नगरीय निकायों की समीक्षा का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में आज दिनभर चली बैठक में सभी नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को बेतरतीब निर्माणों, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पंचायतों के कार्यों और व्यवस्थाओं में कसावट लाने को कहा। साव ने कहा कि काम में लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जवाबदेही तय कर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री साव ने सभी सीएमओ को नई सोच और नई कार्य पद्धति से शहरों तथा शहरवासियों के कल्याण के लिए काम करने को कहा। उन्होंने राज्य के उभरते शहरों को सुव्यवस्थित, सुनियोजित, स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ ही नागरिकों के लिए पर्याप्त जन सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पांचों संभागों के विभागीय क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को हर तिमाही में प्रत्येक नगर पालिका और नगर पंचायत का व्यक्तिगत निरीक्षण कर संचालक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ शशांक पाण्डेय भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री साव ने सभी सीएमओ को आगामी 31 मई तक नगर पंचायतों की नई संपत्तियों पर करारोपण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संग्रहण बढ़ाने संपत्ति कर, जल कर, यूजर चार्ज जैसे करों की वसूली गंभीरता और कड़ाई से करने को कहा। उन्होंने एनर्जी ऑडिट के माध्यम से गैर-जरूरी विद्युत कनेक्शनों की पहचान कर इसके विच्छेदन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकाय के सभी कार्मिकों को हर माह समय पर वेतन और बिजली बिल का भुगतान सुनिश्चित करने को भी कहा।

साव ने जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने के लिए निर्देशित करते हुए शत-प्रतिशत भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण कराने को कहा। उन्होंने 31 मई तक बड़े नाला-नालियों और ड्रेनेज की सफाई के काम पूर्ण करने के साथ ही बरसात में जल भराव रोकने जरूरी उपाय करने को कहा। साव ने सभी सीएमओ को मुख्यालय में ही निवास करते हुए प्रतिदिन प्रात: भ्रमण कर शहर की साफ-सफाई और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भर्ती 2026 : आवेदन 12 मई तक

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर ने महिलाओं के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) के कुल 38 पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, जिनमें अनारक्षित (यूआर) के 19, अनुसूचित जाति (एससी) के 7, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 7, और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 5 पद शामिल हैं।

इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया बीते सोमवार, 20 अप्रैल से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 मई तय की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय लास्ट डेट के शाम 05.00 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं, जिन अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र भरते समय कुछ गलती हो जाएगी, उनके लिए फॉर्म में हुई गलती को सुधार करने का विंडो 13 मई से 15 मई के शाम 05.00 बजे तक सक्रिय रहेगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद अनुसार कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की ग्रेजुएशन डिग्री या द्वितीय श्रेणी ग्रेजुएशन डिग्री और उसी विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए या द्वितीय श्रेणी ग्रेजुएशन डिग्री और डीओई से 'ओ' लेवल पाठ्यक्रम होना अनिवार्य है। वहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस एप्लिकेशन सूट का व्यावहारिक ज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 25,300 से 80,500 रुपए के बीच प्रति माह होगी। वहीं, लिखित परीक्षा रविवार, 28 जून को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.15 बजे के बीच बिलासपुर, रायपुर में आयोजित होने की संभावना है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहां संबंधित पद के लिए जारी आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें। लास्ट में आवेदन पत्र की एक कॉपी भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकाल कर रख लें।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में सूरजपुर प्रदेश में प्रथम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में वित्तीय वर्ष 2024-26 के दौरान प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मंगलवार को यह जानकारी दी गयी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जिले में इस अवधि के दौरान कुल 63 हजार 947 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह उपलब्धि शासन द्वारा जिले के लिए स्वीकृत किए गए कुल 72 हजार 368 आवासों के मुकाबले 88.36 प्रतिशत की कार्य पूर्णता को दर्शाती है। प्रशासनिक स्तर पर की गई सतत मॉनिटरिंग और स्थानीय प्रबंधन के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है।

योजना के अंतर्गत वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राशि का सीधा हस्तांतरण लाभार्थियों के खातों में किया गया है। अब तक आवंटित 868.42 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध

809.23 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों को प्रदान की जा चुकी है, जो कुल बजट का लगभग 93.18 प्रतिशत हिस्सा है। इस प्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रणाली ने निर्माण कार्यों की गति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में प्रगति सुनिश्चित की है।

आगामी चरणों की तैयारी के लिए जिले में 'आवास प्लस 2.0' के तहत नया सर्वे भी पूर्ण कर लिया गया है। इस नवीन सर्वेक्षण में 1.40 लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया है ताकि भविष्य में और अधिक पात्र परिवारों को योजना के दायरे में लाया जा सके। प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से इस योजना को प्राथमिकता दी जा रही है। जमीनी स्तर पर निरंतर निगरानी और हितग्राहियों के सहयोग से सूरजपुर जिला आवास निर्माण की दिशा में राज्य के अन्य जिलों की तुलना में अग्रणी बना हुआ है।

मेडिकल रिपोर्ट निगेटिव फिर भी उम्रकैद बरकरार

बिलासपुर। जस्टिस रमेश सिन्हा और रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी की अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पीड़िता की गवाही स्पष्ट, सुसंगत और भरोसेमंद है, तो उसी आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, भले ही मेडिकल या वैज्ञानिक साक्ष्य आरोपित के पक्ष में क्यों न हों।

यह मामला बेमेतरा जिले का है। पीड़ित बच्ची अपने माता-पिता के काम पर बाहर रहने के दौरान गांव में अपने बड़े पिता के साथ रहती थी। एक दिन वह पड़ोसी के घर गई और देर तक वापस नहीं लौटी। जब उसकी बहन उसे लेने गई, तो बच्ची संदिग्ध स्थिति में मिली। घर लौटने पर उसने बताया कि पड़ोसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना की शिकायत 17 मई 2022 को दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और क्क्ष्टस्ह् एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान मेडिकल परीक्षण में स्पष्ट सबूत नहीं मिले और डीएनए रिपोर्ट भी नकारात्मक रही।

इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता और अन्य गवाहों के बयानों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील करते हुए खुद को निर्दोष बताया। उसने कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है और गवाहों के बयान में विरोधाभास हैं। साथ ही उसने यह भी दलील दी कि वह गूंगा-बहरा और अशिक्षित है, जिससे वह कानूनी प्रक्रिया को समझ नहीं पाया। हाई कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि वैज्ञानिक रिपोर्ट केवल एक राय होती है और मजबूत प्रत्यक्ष गवाही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

भिलाई में नई शराब दुकान का विरोध, विधायक ने सीएम को लिखा पत्र, स्थानांतरण की मांग

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र टाउनशिप के सेक्टर-6 (पश्चिम), वार्ड क्रमांक-63 में प्रस्तावित नई शराब दुकान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय निवासियों के विरोध के बीच, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

देवेन्द्र यादव
विधायक
भिलाई नगर विधानसभा
निवास :- एम.आई.जी. 175-176, एम.पी.हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई-490026 जिला-दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय :- क्वा.नं 5/ए, सड़क नं-41, सेक्टर-5, भिलाई-490006 जिला-दुर्ग (छ.ग.)
फोन नं- 0788-2220330, मो.नं - 8959111115
ई-मेल :- yadavdevendra.nsui@gmail.com
mlabhilai65@gmail.com

अर्ध शास. पत्र क्रमांक /281/VIP/26 भिलाई, दिनांक :- 21/04/2026

प्रति,
श्री विष्णदेव साय जी,
मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- शराब दुकान को सार्वजनिक स्थल से हटाने विषयक।

महोदय जी,

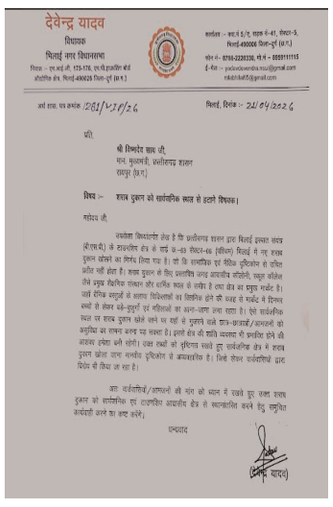

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र (बी.एस.पी.) के टाउनशिप क्षेत्र के वार्ड क.-63 सेक्टर-06 (पश्चिम) भिलाई में नए शराब दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है। जो कि सामाजिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है। शराब दुकान के लिए प्रस्तावित जगह आवासीय कॉलोनी, स्कूल कॉलेज जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल के समीप है तथा क्षेत्र का प्रमुख मार्केट है। जहाँ दैनिक वस्तुओं के अलावा चिकित्सकों का क्लिनिक होने की वजह से मार्केट में दिनभर बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्गों एवं महिलाओं का आना-जाना लगा रहता है। ऐसे सार्वजनिक स्थल पर शराब दुकान खोले जाने पर यहाँ से गुजरने वाले छात्र-छात्राओं/आमजनों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका हमेशा बनी रहेगी। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में शराब दुकान खोला जाना मानवीय दृष्टिकोण से अव्यवहारिक है। जिसे लेकर वार्डवासियों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है।

अतः वार्डवासियों/आमजनों की मांग को ध्यान में रखते हुए उक्त शराब दुकान को सार्वजनिक एवं टाउनशिप आवासीय क्षेत्र से स्थानांतरित करने हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

धन्यवाद

(देवेन्द्र यादव)

आवासीय और शैक्षणिक क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल

विधायक देवेंद्र यादव ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि जिस स्थान पर शराब दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है, वह सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से पूरी तरह अनुचित है। पत्र में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर जोर दिया गया है

शैक्षणिक संस्थान : प्रस्तावित स्थल के निकट स्कूल और कॉलेज स्थित हैं, जहाँ विद्यार्थियों का लगातार आना-जाना बना रहता है।

आवासीय कॉलोनी : यह क्षेत्र पूरी तरह से आवासीय है, जहाँ बड़ी संख्या में परिवार निवास करते हैं।

चिकित्सकीय क्लिनिक : क्षेत्र के मुख्य बाजार में डॉक्टरों के क्लिनिक हैं, जहाँ मरीजों का आना-जाना लगा रहता है।

धार्मिक स्थल : स्थान के समीप ही धार्मिक स्थल होने के कारण क्षेत्र की संवेदनशीलता और भी अधिक बढ़ जाती है।

शांति-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका

विधायक ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सार्वजनिक और व्यस्त स्थल पर शराब की दुकान खुलने से न केवल क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी असुविधा की स्थिति पैदा होगी। उन्होंने इसे मानवीय दृष्टिकोण से पूर्णत: अव्यवहारिक करार दिया है।

सीएम से त्वरित कार्यवाही की उम्मीद

विधायक देवेंद्र यादव ने वार्डवासियों और आम नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस जनहित के मुद्दे पर संज्ञान लें। उन्होंने मांग की है कि उक्त शराब दुकान को तत्काल प्रभाव से आवासीय क्षेत्र से हटाकर किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए ताकि टाउनशिप की शांति और गरिमा बनी रहे।

राइस मिल में लगी आग, लाखों का धान और बारदाना जलकर खाक

कांकेर। जिले के कुलगांव में मंगलवार को अजीबी एग्रो राइस मिल में भीषण आग लग गई। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना में बड़ी मात्रा में बारदाना और धान को नुकसान पहुंचा है। पूरी घटना कोतवाली थाना इलाके की है।

जानकारी के मुतबाकि, सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। वहीं मालिक मोहम्मद आवेश भी राइस मिल पहुंचे हैं। आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद जारी है। घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें धान के बोरों में लगी भ्यावह आग का मंजर नजर आ रहा है।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

राइस मिल मालिक मोहम्मद आवेश ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। चांवल, धान और खाली बोरे सभी कुछ जल गया है। नुकसान का अभी आकलन नहीं किया जा सकता है।

'पुल बनाओ या रास्ता खोलो'...नेशनल हाईवे-130 पर चक्काजाम, स्कूल ड्रेस में बच्चों ने संभाला मोर्चा

गरियाबंद। मैनपुर ब्लॉक के अमाड़ पंचायत के सैंकड़ों ग्रामीणों ने मंगलवार को पुलिया निर्माण की मांग को लेकर नेशनल हाइवे-130 पर चक्काजाम कर दिया है। भारी संख्या में आश्रित ग्रामों की महिलाएं और स्कूली बच्चे जुगाड़ के पास पहुंचकर चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं.

उनका कहना है कि पुल निर्माण के नाम पर पुराने रपटे को तोड़ दिया गया, जिससे आने वाले मानसून सीजन में ग्रामीणों की आवाजाही पर गंभीर असर पड़ सकता है. मांग की थी कि बारिश के पूर्व उनके मार्ग में तोड़े गए पुल को आवाजाही लायक ही बना दिया जाए, ताकि रोजमार्रा के काम और स्कूली बच्चों को आने-जाने में परेशानी ना हो, लेकिन सुस्त प्रशासन ने पहल नहीं की. इससे पहले 30 मार्च को ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर अपनी समस्या से अवगत कराया था।

स्कूली बच्चे भी हुए शामिल

इस नेशनल हाइवे पर बैठे ग्रामीणों के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की सूचना कलेक्टर को 15 दिन पूर्व दी गई थी। बड़ी संख्या में स्कूल ड्रेस में बच्चे और महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर शामिल हुई हैं। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम

का कहना है कि प्रशासन आदिवासी अंचल के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। उनका कहना है कि बारिश के दौरान स्कूली बच्चों और प्रसूताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

एनओसी का हवाला देकर रुकवा दिया काम

दरअसल, नेशनल हाईवे से अमाड़ को जोड़ने वाले मार्ग पर पट्टाबहाल नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए वर्ष 2024 में विशेष केंद्रीय सहायता मद से 1.49 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी. इस कार्य के लिए पीएमजीएसवाय विभाग को एजेंसी बनाया गया और एमएस नमन कंस्ट्रक्शन से अनुबंध किया गया। ठेका कंपनी ने फरवरी माह में काम शुरू करते हुए पहले से मौजूद रपटे को तोड़ दिया और नींव की खुदाई भी शुरू कर दी थी। फिलहाल नाले पर केवल कच्ची मिट्टी और रेत से अस्थाई रपटा बनाया गया है, जो हल्की बारिश में बह जाने की आशंका है। हालांकि, उदंती अभ्यारण्य प्रशासन ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) का हवाला देते हुए काम रुकवा दिया। प्रशासनिक तालमेल के अभाव में निर्माण कार्य अधर में लटक गया, जिसका खामियाजा अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि बरसात से पहले कम से कम रपटे की मरम्मत कर आवाजाही सुचारू की।

राजस्थान : पचपदरा रिफाइनरी आग मामले की जांच शुरू

जयपुर। राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी यूनिट में हुई आग की घटना की वजह की जांच करने के लिए मंगलवार को कई जांच और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं। वहीं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके का दौरा किया। इस घटना के चलते प्रधानमंत्री मोदी का रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए तय दौरा टाल दिया गया।

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, हीट एक्सचेंजर सर्किट में हाइड्रोकार्बन लीक होने के चलते क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू) में आग लग गई। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों ने करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। रिफाइनरी का संचालन करने वाली कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने पुष्टि की कि एहतियात के तौर पर प्रभावित सभी यूनिटों को तुरंत अलग कर दिया गया था। कंपनी ने बताया कि आग एक खास हिस्से तक ही सीमित रही और अब तक किसी बड़े ढांचे को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। इस घटना के बाद, आग लगने की वजह की गहन जांच करने और संचालन पर पड़ने वाले संभावित असर का आकलन करने के लिए आंतरिक विशेषज्ञों, बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें तैनात की गई हैं।

इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की। रिफाइनरी परिसर के अंदर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और एहतियात के तौर पर वहां आने-जाने पर रोक लगा दी गई है।

लगभग 79,459 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनी यह रिफाइनरी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है। उद्घाटन समारोह को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया गया है।

अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि मामले की विस्तृत जांच चल रही है और जैसे-जैसे जानकारी मिलेगी, आगे की अपडेट साझा की जाएंगी। उद्घाटन समारोह के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थीं। लगभग 2,00,000 लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया था।

बंगाल में हमारे पक्ष में होंगे परिणाम, हमारी पांच गारंटियां जनता को पसंद आ रही हैं : सचिन पायलट

मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पार्टी उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी के समर्थन में एक रोड शो किया।

मुर्शिदाबाद में आईएएनएस से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि यह बदलाव का चुनाव है। लोग राज्य और केंद्र, दोनों सरकारों से तंग आ चुके हैं और वे बदलाव की तलाश में हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पारंपरिक रूप से मजबूत रही है। हमारा मानना है कि इस चुनाव में बदलाव जरूर आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को कई मौके दिए गए हैं। राज्य सरकार को तीन कार्यकाल और केंद्र सरकार को तीन कार्यकाल। इतने मौके देने के बाद भी बंगाल पिछड़ा हुआ है। यहां बेरोजगारी और गरीबी है। पहले बंगाल बहुत आगे हुआ करता था, लेकिन आज वह पीछे रह गया है। इसी कारण लोग एक विकल्प की तलाश में हैं। कांग्रेस के शासन में बंगाल ने हमेशा विकास देखा है। जब यहां कांग्रेस सरकार थी तो उद्योग, निवेश, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में बंगाल को प्राथमिकता मिलती थी। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी पांच गारंटियां जनता को पसंद आ रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुर्शिदाबाद में कहा कि भाजपा सरकार महिला आरक्षण के जरिए धोखा देने की कोशिश कर रही है। तीन साल पहले बिल पास हो चुका था, फिर भी लागू क्यों नहीं किया गया? अब परिसीमन के नाम पर सीटों में हेर-फेर करने के लिए बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन जनता इसे पूरी तरह एक्सपोज कर चुकी है। तीन साल पहले जब बिल पास किया गया तो पूरी संसद ने इसका समर्थन किया था। फिर तीन साल तक इंतजार क्यों किया? आज प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि अगर केंद्र सरकार आज बिल लाए तो मौजूदा लोकसभा में एक-तिहाई सीटें महिलाओं को देने के लिए पूरा विपक्ष तैयार है।

मैड्रिड ओपन 2026 : फैंस को झटका, चोट के कारण टूर्नामेंट से हटीं अनिसिमोवा और अलेक्जेंड्रोवा

मैड्रिड। वर्ल्ड नंबर-6 अमांडा अनिसिमोवा और मनंबर-14 एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा चोट के कारण मुतुआ मैड्रिड ओपन 2026 से हट गई हैं। दो बार की मेजर फाइनलिस्ट अनिसिमोवा कलाई की चोट से पीड़ित हैं, जबकि अलेक्जेंड्रोवा की पीठ के निचले हिस्से में चोट है। अलेक्जेंड्रोवा की जगह ड्रॉ में मारिया सक्कारी को नंबर 33 वरीयता दी गई। वहीं, महिलाओं के सिंगल्स ड्रॉ के निचले हिस्से में क्वार्टरफाइनल से पहले मजबूत दावेदार मानी जा रही अनिसिमोवा की जगह मैग्डालेना फ्रेच को नंबर 34 सीड बनाया गया। दोनों खिलाड़ियों को पहले दौर में बाई मिली है।

सक्कारी और फ्रेच के मूल पहले दौर के प्रतिद्वंद्वी जेनिस जेन और कैटरीना सिनियाकोवा अब अंतिम क्वालिफाइंग दौर के बाद तय होने वाले क्वालीफायर या 'लकी लूजर' खिलाड़ियों से मुकाबला करेंगी, जिनका चयन अंतिम क्वालीफाइंग दौर के समापन पर ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। अनिसिमोवा ने मियामी में बेलिंडा बेनसिक से चौथे दौर में हारने के बाद से कोई मुकाबला नहीं खेला है। इसके बाद एक अज्ञात चोट के कारण वह चार्ल्सटन टूर्नामेंट से भी हट गई थीं। अलेक्जेंड्रोवा भी पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण चार्ल्सटन से हट गई थीं। वह दो सप्ताह पहले ही कोर्ट पर लौटी थीं, लेकिन लिंज में अपने पहले ही मुकाबले में कैरोलिना प्लिस्कोवा से हार गईं, और स्टटगार्ट में दूसरे दौर में लिंडा नोस्कोवा से हारकर बाहर हो गईं।

मुख्य ड्रॉ घोषित होने से पहले मैड्रिड से हटने वाली अन्य खिलाड़ियों में ग्रेट ब्रिटेन की सोनाय कार्टल शामिल हैं, जो पीठ की चोट के कारण पूरे क्ले-कोर्ट सीजन में नहीं खेल पाएंगी। फ्रांस की वारवारा ग्राचेवा मार्च के अंत में अभ्यास के दौरान एसीएल में चोट लगने के कारण पूरे क्ले-कोर्ट सीजन से बाहर हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की माया जॉइंट पीठ की चोट के कारण नहीं खेल पाएंगी। एम्मा नवारो लगातार बीमारी के कारण बाहर हैं। एम्मा राडुकानु और मार्केटा वोंद्रोसोवा भी इस सूची में शामिल हैं। कुल 96 महिला खिलाड़ियों को अब 'काजा मैजिका' में खिताब तक पहुंचने का रास्ता पता चल गया है। सीजन के सबसे कठिन टूर्नामेंट्स में शामिल इस प्रतियोगिता के अंतिम दौर के मुकाबले भव्य मनोलो सैन्टाना स्टेडियम में खेले जाएंगे, जहां मैड्रिड में दुनिया की बेहतरीन डब्ल्यूटीए खिलाड़ी उतरने को तैयार हैं। डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका का लक्ष्य काजा मैजिका में चौथा खिताब जीतने वाली पहली महिला बनना है।

ऐसा होने पर वह इस टूर्नामेंट

आईटी विभाग ने उदयनिधि के चुनावी हलफनामों में विसंगतियों गिनाईं, मद्रास हाई कोर्ट ने मामला किया स्थगित

चेन्नई। आयकर विभाग ने मद्रास हाई कोर्ट को उदयनिधि स्टालिन के चुनावी हलफनामों में स्पष्ट विसंगतियों के बारे में सूचित किया है। इसमें विशेष रूप से 2021 और 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान निवेश, ऋण और वित्तीय खुलासों के संबंध में जानकारी है। अब इस मामले की सुनवाई चार हफ्तों के लिए टाल दी गई है।

विभाग ने कोर्ट में दायर एक जवाबी हलफनामे में कहा कि रेड जायंट मूवीज में 7.36 करोड़ रुपए का निवेश, जिसका खुलासा स्टालिन ने अपने 2021 के हलफनामे में किया था, उनके 2026 के घोषणापत्र में दिखाई नहीं देता है। साथ ही, नवीनतम हलफनामे में उसी कंपनी में उनकी पत्नी के नाम पर 2.63 करोड़ रुपए के निवेश का उल्लेख है, जिसकी जानकारी पहले नहीं दी गई थी।

विभाग ने बताया कि ये अंतर, वित्तीय रिकॉर्ड में अन्य विसंगतियों के साथ मिलकर, इस चरण में किसी भी निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल बनाते हैं। यह हलफनामा आयकर महानिदेशक (जांच), तमिलनाडु और पुडुचेरी की ओर से प्रस्तुत किया गया था। इस दौरान ऋण संबंधी खुलासों को लेकर भी सवाल उठाए गए। जहां स्टालिन के 2026 के हलफनामे में 10 करोड़ रुपए के ऋण का उल्लेख है, वहीं 2021 की फाइलिंग में लगभग 11.06 करोड़ रुपए की देनदारियों को दर्ज किया गया था। हालांकि, कंपनी के वित्तीय विवरण लगभग 17.69 करोड़ रुपए के उधार का संकेत देते हैं। विभाग ने कहा कि विस्तृत और पूर्ण रिकॉर्ड तक पहुंच के बिना, इन आंकड़ों का सटीक मिलान करना संभव नहीं है। मामले को और अधिक जटिल बनाते हुए, विभाग ने पाया कि आयकर रिटर्न आईटीआर-2 प्रारूप का उपयोग करके दाखिल किए गए थे, जिसमें बैलेंस शीट जमा करना अनिवार्य नहीं है।

परिणामस्वरूप, निवेश और देनदारियों का स्वतंत्र सत्यापन सीमित रहता है। हलफनामे में दस्तावेजीकरण में कमियों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें कुछ संस्थाओं के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों की अनुपस्थिति भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसमें उल्लेख किया गया कि स्टालिन की पत्नी ने संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था, जिससे संबंधित वित्तीय प्रविष्टियों की जांच सीमित हो गई।

उत्तर कोरिया ने ब्रिटेन और इंडोनेशिया में नए राजदूत किए नियुक्त

प्योंगयांग। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन और इंडोनेशिया के लिए नए राजदूत नियुक्त करने का ऐलान किया। करीब 10 वर्षों में यह पहली बार है जब प्रमुख राजनयिक केंद्रों पर उसके राजदूत बदले गए हैं।

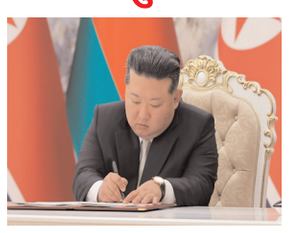

मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने बताया कि, मुन म्योंग-सिन को ब्रिटेन में प्योंगयांग का दूत नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती चो इल की जगह ली है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग एक दशक में यह पहला बड़ा फेरबदल है।

मुन पहले लंदन में उत्तर कोरियाई दूतावास में ते योंग-हो के साथ काम कर चुके हैं। ते योंग-हो भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। ते ने राजनयिक मिशन में उत्तर कोरियाई मंत्री के तौर पर काम किया था। वहीं, उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने इंडोनेशिया में अपने नए शीर्ष दूत के तौर पर होंग क्वांग-इल की नियुक्ति का भी ऐलान किया। वह दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के राजदूत का पद भी संभालेंगे। 2015 के बाद पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने इंडोनेशिया में तैनात अपने शीर्ष राजनयिक की नियुक्ति को लेकर कोई औपचारिक घोषणा की है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर कोरिया ने 12 अप्रैल को बेलारूस में भी एक नया राजदूत भेजा है। इसे पिछले महीने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की प्योंगयांग यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का संकेत माना जा रहा है।

`कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार, बाहरी आर्थिक संबंधों के पूर्व उप मंत्री जी क्योंग-सु ने लुकाशेंको को अपना परिचय पत्र सौंपा। इस समारोह के दौरान जी ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन की ओर से 'शुभकामनाएं' दीं, जिसके लिए लुकाशेंको ने आभार व्यक्त किया।

ताशकंद वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी करेगा

मुंबई। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स (डब्ल्यूपीए) ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के लिए ताशकंद को मेजबान शहर के तौर पर चुना है। पहली बार यह प्रतिष्ठित इवेंट उज्बेकिस्तान और मध्य एशिया में आयोजित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा एकल पैरा खेल इवेंट जून 2027 में ओलंपिक सिटी मेन स्टेडियम में आयोजित होगा।

इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने मंगलवार को एक प्रेस रिलीज में बताया कि ताशकंद में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का 13वां संस्करण आयोजित होगा। ऐसा पांचवीं बार होगा, जब यह इवेंट एशिया में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले दोहा 2015, दुबई 2019, कोबे 2024 और नई दिल्ली 2025 में यह इवेंट हो चुका है।100 से ज्यादा देशों के लगभग 1,300 एथलीट्स के शामिल होने की उम्मीद के साथ, यह चैंपियनशिप देश में अब तक आयोजित होने वाला सबसे बड़ा इंटरनेशनल पैरा खेल इवेंट बनने जा रहा है। हालांकि, इवेंट्स की आखिरी संख्या अभी पक्की नहीं हुई है, लेकिन प्रोग्राम में कम से कम 164 इवेंट शामिल होंगे, जो पैरालंपिक खेलों के प्रोग्राम के हिसाब से होंगे। इसमें कुछ और इवेंट्स भी शामिल हो सकते हैं।

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के प्रमुख पॉल फिट्जगेराल्ड ने देश और इस इलाके, दोनों के लिए इस इवेंट के महत्व पर कहा, 'हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होगी। यह देश में अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पैरा-खेल इवेंट होगा, जो हमारे खेल और हमारे फैन बेस को बढ़ाने के साथ-साथ मध्य एशिया में दिव्यांग लोगों के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए बड़े मौके खोलेगा।'

फिट्जगेराल्ड ने पैरा-एथलेटिक्स में उज्बेकिस्तान की हाल की तरक्की की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में, उज्बेकिस्तान ने पैरा एथलेटिक्स में एक उभरते हुए एशियाई देश के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। उनके एथलीट्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप और पैरालंपिक खेलों में लगातार बेहतर नतीजे दिए हैं, जो सुविधाओं को बेहतर बनाने और खेल में निवेश करने के लिए उज्बेकिस्तान की नेशनल पैरालंपिक कमेटी की कोशिशों को दिखाता है। हमें पूरा भरोसा है कि आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप न सिर्फ इस देश में, बल्कि पूरे इलाके में एक यादगार छाप छोड़ेगी।'

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का सबसे हालिया संस्करण भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जहां 100 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने 186 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। ब्राजील ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। इस देश ने कुल 44 पदक जीते, जिनमें 15 गोल्ड, 20 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। चीन 52 पदकों (13 स्वर्ण सहित) के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि उज्बेकिस्तान 5 गोल्ड के साथ शीर्ष 15 में शामिल रहा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का सबसे हालिया संस्करण भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जहां 100 से ज्यादा देशों के 1,000 से ज्यादा एथलीट्स ने 186 मेडल इवेंट्स में हिस्सा लिया। ब्राजील 44 मेडल्स के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा, जिसमें 15 गोल्ड, 20 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। चीन 52 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 13 गोल्ड मेडल शामिल थे, जबकि उज्बेकिस्तान 5 गोल्ड मेडलों के साथ शीर्ष 15 में जगह बनाने में सफल रहा।

नए वैश्विक माहौल में भारत-कनाडा व्यापार वार्ता का बढ़ा महत्व

नई दिल्ली। भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता अतीत में दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण बाधित हुई थी, लेकिन इस साल मार्च में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान बातचीत फिर शुरू होने से दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध बनाने का नया मौका मिला है। यह बात कनाडा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कही है।

कनाडा में पूर्व उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने इंडिया नैरिटिव में एक लेख में कहा, 'कनाडा एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। भू-राजनीतिक अनिश्चितता के इस दौर में उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है, जो अब एक रणनीतिक समस्या बनती जा रही है। ऐसे में कनाडा के लिए अपने व्यापार को विविध बनाना जरूरी हो गया है। इस संदर्भ में भारत न सिर्फ एक बाजार है, बल्कि एक लंबे समय का रणनीतिक साझेदार भी है।' उनका मानना है कि 2022 में अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट (ईपीटीए) की ओर बढ़ना एक व्यावहारिक कदम था, जिसकी पहले कमी थी। इसी आधार पर आगे चलकर एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीईपीए को एक बार में पूरा होने वाले समझौते के रूप में नहीं, बल्कि चरणों में आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। पहले चरण में ईपीटीए के तहत हुई बातचीत को मजबूत किया जा सकता है। इसके बाद निवेश सुरक्षा, डिजिटल व्यापार और नियामक सहयोग जैसे जटिल मुद्दों को धीरे-धीरे शामिल किया जा सकता है। कृषि, बौद्धिक संपदा और सरकारी खरीद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बाद में चर्चा की जा सकती है, जब माहौल अनुकूल हो। लेख में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार अभी कम है, लेकिन बेहतर बाजार पहुंच और आसान नियमों से इसे बढ़ाया जा सकता है। सेवाओं का व्यापार पहले से मजबूत है और इसे आईटी, शिक्षा और प्रोफेशनल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में और बढ़ाया जा सकता है। कस्टम्स प्रक्रिया को आसान बनाकर व्यापार लागत कम की जा सकती है और प्रक्रिया को अधिक भरोसेमंद बनाया जा सकता है। लेख में यह भी बताया गया है कि दोनों देशों के बीच निवेश संबंध पहले से मजबूत हैं। कनाडा के पेंशन फंड और निवेशकों ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में बड़ा निवेश किया है, जबकि भारतीय कंपनियां कनाडा के सेवा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं।

गुवाहाटी हाई कोर्ट में पवन खेड़ा की जमानत पर सुनवाई, उच्च न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखा

गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला असम पुलिस ने दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने तीखे और एक-दूसरे से बिल्कुल अलग तर्क पेश किए।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वकील कमल नारायण चौधरी के साथ मिलकर दलील दी कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और बदले की भावना से किया गया है।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं है और इनका मकसद एक राजनीतिक विरोधी की आवाज दबाना है।

इस अर्जी का विरोध करते हुए, असम पुलिस की तरफ से पेश हुए असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सैकिया ने कहा कि खेड़ा गंभीर अपराधों में शामिल हैं, जिनमें जालसाजी और धोखाधड़ी शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच में पहली नजर में ऐसे सबूत मिले हैं, जो जानबूझकर की गई गलत हरकतों की ओर इशारा करते हैं। इसलिए, हिरासत में पूछताछ और जमानत न देना सही है।देश सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा पवन खेड़ा को दी गई राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला मुख्यमंत्री हिमंता बिस?वा सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा के खिलाफ पवन खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। खेड़ा ने पहले आरोप लगाया था कि रिंकी भुइयां सरमा का व्योमिंग स्थित एक अमेरिकी कंपनी से संबंध है। उन्होंने मुख्यमंत्री सरमा और उनके परिवार से जुड़ी बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का दावा किया था।

संपादकीय

बदलती प्राथमिकताओं और वैश्विक उथल-पुथल के बीच यूरोपीय संघ और बांग्लादेश ने अपनी साझेदारी को फिर से संतुलित किया

नवाब खान

यूरोपीय संघ और बांग्लादेश ने 20 अप्रैल को ब्रसेल्स में साझेदारी और सहयोग समझौते (PCA) पर प्रारंभिक हस्ताक्षर किए, जो उनके संबंधों को केवल व्यापार-आधारित रिश्तों से आगे बढ़ाकर एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का संकेत देता है। यह समझौता ढाका में राजनीतिक बदलाव के बाद एक पुनर्संतुलन को भी दर्शाता है, जब 2026 के चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की निर्णायक जीत हुई और अगस्त 2025 में शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला। इस समझौते को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश यूरोपीय संघ के साथ PCA पर हस्ताक्षर करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बनने की ओर बढ़ रहा है, जिसके वैश्विक प्रभाव होंगे। पश्चिमी देशों के साथ BNP के पुराने तनाव और शासन संबंधी चिंताओं को देखते हुए ब्रसेल्स प्रक्रियात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि काजा कैलास और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने PCA समझौते पर प्रारंभिक हस्ताक्षर किए। प्रेस से बातचीत में कैलास ने कहा कि यह समझौता 'हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है' और उन्होंने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के एक प्रमुख साझेदार के साथ संबंधों को और गहरा करने की उम्मीद जताई। उन्होंने नई सरकार को 'महत्वाकांक्षी सुधारों' के लिए बधाई भी दी। रहमान ने कहा कि यह समझौता ऐसे समय में आया है जब 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि दोनों पक्ष समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।'

बांग्लादेश का बढ़ता महत्व

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर भी बैठक में मौजूद थे। यह समझौता इस व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है कि दक्षिण एशिया वैश्विक रणनीति का केंद्र बनता जा रहा है। बांग्लादेश जैसे देश अब केवल 'विकासशील अर्थव्यवस्थाएं' नहीं हैं, बल्कि बड़े विनिर्माण केंद्र, विशाल उपभोक्ता बाजार और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। PCA राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और महत्वाकांक्षी ढांचा प्रदान करता है, जो लोकतंत्र, मानवाधिकार, शांति और सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के साझा मूल्यों पर आधारित है। 82 अनुच्छेदों वाले इस समझौते के तहत राजनीतिक संवाद, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, परिवहन, कृषि, प्रवासन, सुरक्षा, वित्त, समुद्री मामलों और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। इस पाठ पर प्रारंभिक हस्ताक्षर होने के बाद, दोनों पक्षों द्वारा औपचारिक हस्ताक्षर और अनुमोदन का रास्ता खुल गया है। लागू होने के बाद यह 2001 के सहयोग समझौते की जगह लेगा। दोनों पक्ष इसे भविष्य उन्मुख और व्यापक समझौता मानते हैं, जो केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। ऐतिहासिक रूप से, यूरोपीय संघ और बांग्लादेश के संबंध व्यापार पर आधारित रहे हैं। यूरोपीय संघ बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, खासकर वस्त्र क्षेत्र में। लेकिन अब यह संबंध नए आयाम ले रहा है। बांग्लादेश 'अल्प विकसित देश' (LDC) की श्रेणी से बाहर निकलने की दिशा में बढ़ रहा है और GSP+ व्यापार सुविधाओं की ओर बढ़ रहा है। यूरोपीय संघ श्रम और शासन से जुड़े सुधारों पर जोर दे रहा है ताकि GSP+ (जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेज) के तहत व्यापार लाभ जारी रह सकें, जबकि ढाका निरंतर बाजार पहुंच और निवेश चाहता है।

संबंधों का अहम मोड़

यूरोपीय संघ अब कानून के शासन, श्रम मानकों, लोकतांत्रिक शासन और भ्रष्टाचार विरोध पर अधिक जोर दे रहा है। मुख्य मतभेद यह है कि जहां यूरोपीय संघ खुद को मूल्यों पर आधारित मानता है, वहीं नई बांग्लादेश सरकार अभी सत्ता को मजबूत करने की प्रक्रिया में है।यूरोपीय संघ 'प्रबंधित प्रवासन' ढांचे को बढ़ावा दे रहा है, जबकि बांग्लादेश कानूनी श्रम गतिशीलता के रास्ते चाहता है। ब्रसेल्स की रुचि केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि भू-राजनीतिक भी है— बांग्लादेश को तेजी से बढ़ते विनिर्माण केंद्र, चीन-केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकल्प और क्षेत्रीय संतुलन के रूप में देखा जा रहा है।नई बांग्लादेश सरकार भारत के साथ संबंधों को फिर से संतुलित करने की कोशिश कर रही है, जबकि चीन के साथ करीबी संबंध भी बनाए हुए है। यूरोपीय संघ का दृष्टिकोण बांग्लादेश को नियम-आधारित बहुपक्षीय ढांचे में जोड़ने का है, न कि सीधे प्रतिस्पर्धा करने का। हालांकि सकारात्मक प्रगति के बावजूद कुछ संरचनात्मक जोखिम बने हुए हैं— बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति, ध्रुवीकरण, संस्थागत कमजोरी और लोकतांत्रिक गिरावट को लेकर यूरोपीय संघ की चिंताएं।

साइबर अपराध का बदलता चेहरा

महेन्द्र तिवारी

डिजिटल युग ने मानव जीवन को जितना सरल और सुविधाजनक बनाया है, उतना ही जटिल और जोखिमपूर्ण भी बना दिया है। आज बैंकिंग से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, खरीदारी और संचार तक लगभग हर काम इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से हो रहा है। इस तेज बदलाव के बीच अपराधियों ने भी अपने तरीके बदल लिए हैं। पहले जहां चोरी और धोखाधड़ी के लिए भौतिक उपस्थिति जरूरी होती थी, वहीं अब एक मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति किसी को भी ठग सकता है। हाल के वर्षों में डिजिटल ठगी के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है और चिंता की बात यह है कि इनका शिकार केवल अनपढ़ या ग्रामीण लोग ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षित और समझदार लोग भी हो रहे हैं।

डिजिटल ठगी के नए तरीकों में सबसे खतरनाक रूप से उभर कर सामने आया है तथाकथित डिजिटल अरेस्ट। यह एक ऐसा छल है जिसमें अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, जांच एजेंसी का कर्मचारी या किसी सरकारी विभाग का प्रतिनिधि बताकर व्यक्ति को डराता है। उसे बताया जाता है कि उसके नाम पर कोई गंभीर अपराध दर्ज है जैसे धन शोधन, अवैध लेनदेन या किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता। इसके बाद वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के माध्यम से व्यक्ति को कई घंटों तक अपने नियंत्रण में रखा जाता है। उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह जांच के दायरे में है और उसे कहीं जाने या किसी से बात करने की अनुमति नहीं है। इस दौरान उसे मानसिक दबाव में रखा जाता है और अंतत: पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में साइबर अपराध के लगभग 15 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर लगभग 20 लाख के आसपास पहुंच गई। इनमें से एक बड़ा हिस्सा वित्तीय ठगी से जुड़ा है। औसतन हर दिन हजारों लोग इस तरह के अपराधों का शिकार हो रहे हैं। कई मामलों में एक ही व्यक्ति से 50000 से लेकर 5000000 रुपये तक की ठगी की गई है। यह आंकड़े केवल दर्ज मामलों के हैं, वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि बहुत से लोग शर्म या डर के कारण शिकायत ही नहीं करते।

डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटाले इतने प्रभावी इसलिए होते हैं क्योंकि वे मानव मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब किसी व्यक्ति को अचानक यह बताया जाता है कि वह किसी गंभीर अपराध में फंस गया है, तो उसका पहला भाव डर और घबराहट का होता है। अपराधी इसी डर का फायदा उठाते हैं। वे अपनी भाषा, पहनावा और संवाद शैली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उन्हें वास्तविक अधिकारी समझने लगता है। कई बार वे नकली पहचान पत्र, कार्यालय का बैकग्राउंड और वर्दी का भी उपयोग करते हैं ताकि उनकी बात और अधिक विश्वसनीय लगे।

इस प्रकार की ठगी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें समय का दबाव बनाया जाता है। पीड़ित को सोचने या सलाह लेने का अवसर नहीं दिया जाता। उसे कहा जाता है कि यदि उसने तुरंत सहयोग नहीं किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मानसिक दबाव में व्यक्ति बिना सत्यापन किए ही पैसे भेज देता है। यह स्थिति दर्शाती है कि केवल तकनीकी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिक सजगता और धैर्य भी उतना ही आवश्यक है।

भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा 1930 हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है जहां तुरंत सहायता प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न राज्यों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं और डिजिटल जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद अपराधों की संख्या में कमी नहीं आ रही है, जिसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी और तकनीक का तेजी से बदलता स्वरूप है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल ठगी को रोकने के लिए केवल कानून और तकनीक पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए समाज के हर वर्ग को जागरूक करना आवश्यक है। परिवारों में इस विषय पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, खासकर बुजुर्गों और युवाओं को इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। स्कूल और कॉलेज स्तर पर भी साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी शुरुआत से ही सतर्क रहे।

व्यक्तिगत स्तर पर कुछ सरल सावधानियां अपनाकर इस प्रकार की ठगी से बचा जा सकता है। सबसे पहले किसी भी अनजान कॉल या संदेश पर तुरंत विश्वास न करें। यदि कोई खुद को अधिकारी बताकर डराने की कोशिश करता है तो उसकी पहचान की पुष्टि करें। किसी भी स्थिति में अपने बैंक खाते, पासवर्ड, ओटीपी या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। यदि कोई आपसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता है तो पहले अपने परिवार या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें। याद रखें कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से पैसे नहीं मांगती।

डिजिटल ठगी का बढ़ता हुआ खतरा केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक विश्वास को भी कमजोर करता है। जब लोग बार बार ऐसे अपराधों का शिकार होते हैं तो उनका विश्वास संस्थाओं और तकनीक दोनों से उठने लगता है। यह स्थिति विकास की गति को भी प्रभावित कर सकती है क्योंकि डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में लोग हिचकिचाने लगते हैं।

इस समस्या का समाधान केवल तकनीकी उपायों में नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी में निहित है। सरकार, संस्थाएं और आम नागरिक सभी को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। जागरूकता, सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ही इस लड़ाई के सबसे प्रभावी हथियार हैं। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो डिजिटल ठगी का यह जाल और अधिक व्यापक और खतरनाक हो सकता है।

अंतत: यह समझना जरूरी है कि डिजिटल युग में सुरक्षा केवल पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है। जितना हम तकनीक का उपयोग करते हैं, उतना ही हमें उसके जोखिमों को समझना भी आवश्यक है। सावधानी और समझदारी के साथ ही हम इस अदृश्य खतरे से स्वयं को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकते

क्यों भारत के भविष्य का नेतृत्व महिलाओं को करना चाहिए

डॉ. पी टी ऊषा

मैंने अपना पूरा जीवन भागदौड़ में ही बिताया है, पहले केरल की कच्ची सड़कों पर, फिर वैश्विक मंचों पर और अब सार्वजनिक जीवन के गलियारों में। हर कदम पर मुझे कई मुश्किलो का सामना करना पड़ा है, कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अनकही बाधाओं का भी, जिन्होंने महिलाओं को यह बताया कि उनका यहाँ कोई स्थान नहीं है। मैंने यह भी देखा है कि जब ये बाधाएं टूटने लगती हैं तो क्या होता है। अवसर परिणामों को बदल देता है और इससे भी ज़रुरी बात यह है कि यह लोगों की सोच को बदल देता है।

यही कारण है कि संविधान (एक सौ अट्ठाईसवाँ संशोधन) विधेयक, 2023—नारी शक्ति वंदन अधिनियम—केवल एक विधायी उपलब्धि नहीं है। यह एक लंबे समय से प्रतीक्षित संरचनात्मक सुधार है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना न तो कोई रियायत है और न ही दिखावा। यह अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी लोकतंत्र की दिशा में एक ज़रुरी कदम है।

खेलों ने हमें क्या सिखाया है

जब मैंने 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में हिस्सा लिया और कुछ ही सेकंड के अंतर से पदक से चूक गई, तब बहुत कम भारतीय लड़कियां थीं, जो वैश्विक मंच पर खुद को देख पाती थीं। लेकिन पिछले कई दशकों में यह स्थिति बदली है। प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और पहचान तक पहुंच में सुधार के साथ, भारतीय महिलाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता हासिल करने लगीं है।

पी.वी. सिंधु, मीराबाई चानू, विनेश फोगाट और मैरी कॉम जैसी एथलीटें अकेले नहीं उभरीं। वे एक ऐसी व्यवस्था का परिणाम हैं, जिसने धीरे-धीरे ही सही, पहुंच को व्यापक बनाना शुरू किया। प्रतिनिधित्व आकांक्षाएं पैदा करता है और आकांक्षा, जब समर्थित होती है, तो उपलब्धि दिलाती है।

सबक साफ है। जब महिलाओं को स्थान दिया जाता है, तो वे व्यवस्था में केवल भाग नहीं लेतीं, वे शानदार प्रदर्शन भी कर दिखाती हैं।

हर भारतीय के लिए बेहतर शासन

भारत में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व का प्रभाव पहले ही देखा जा चुका है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किए जाने के बाद से, विभिन्न राज्यों में किए गए कई अध्ययनों से पता चला है कि महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व वाले क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार हुआ है।

ये महज़ 'महिलाओं के मुद्दे' नहीं हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं। महिला नेता अक्सर सुरक्षित सार्वजनिक स्थान, सुचारू रूप से चलने वाले स्कूल, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी शासन से जुड़ी उन रोजमर्रा की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो परिवारों और समुदायों को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं।

इस प्रतिनिधित्व को राज्य विधानसभाओं और संसद तक विस्तारित करना केवल निष्पक्षता की बात नहीं है। यह शासन की गुणवत्ता में सुधार से जुड़ा है।

प्रतिनिधित्व का आर्थिक महत्व

भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी विश्व में सबसे कम है, जो लगभग 25 प्रतिशत के आसपास है। यह केवल एक सामाजिक चिंता नहीं, बल्कि एक आर्थिक समस्या भी है।

विधानसभाओं में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व उन नीतियों को प्राथमिकता देने में मदद कर सकता है, जो इस अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करती हैं, जैसे किफायती बाल देखभाल, सुरक्षित कार्यस्थल, ऋण तक पहुंच और महिला उद्यमियों के लिए समर्थन। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से भारत की जीडीपी में 700 बिलियन डॉलर तक की वृद्धि हो सकती है।

अधिक समावेशी संसद न केवल एक लोकतांत्रिक आवश्यकता है, बल्कि एक आर्थिक अनिवार्यता भी है।

बोध कथा

जो प्राप्त है, पर्याप्त है

मन में जब तक चिन्ताओ का कूड़ा-कचरा और

बुरे संस्करो का गोबर भरा है, तब तक उपदेशामृत का कोई लाभ न होगा।

ए क बार एक स्वामी जी भिक्षा माँगते हुए एक घर के सामने खड़े हुए और उन्होंने आवाज लगायी, भिक्षा दे दे माते! घर से महिला बाहर आयी। उसने उनकी झोली मे भिक्षा डाली और कहा, 'महात्माजी, कोई उपदेश दीजिए!' स्वामीजी बोले, 'आज नहीं, कल दूँगा। कल खीर बना के देना।' दूसरे दिन स्वामीजी ने पुन उस घर के सामने आवाज दी - भिक्षा दे दे माते! उस घर की स्त्री ने उस दिन खीर बनायीं, जिसमे बादाम-पिस्ते भी डाले थे। वह खीर का कटोरा लेकर बाहर आयी। स्वामी जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया। वह स्त्री जब खीर डालने लगी, तो उसने देखा कि कमंडल में गोबर और कूड़ा भरा पड़ा है। उसके हाथ ठिठक गए। वह बोली, 'महाराज ! यह कमंडल तो गन्दा है।' स्वामीजी बोले, 'हाँ, गन्दा तो है, किन्तु खीर इसमें डाल दो।'स्त्री बोली, 'नहीं महाराज, तब तो खीर खऱाब हो जायेगी। दीजिये यह कमंडल, में इसे शुद्ध कर लाती हूँ।' स्वामीजी बोले, मतलब जब यह कमंडल साफ़ हो जायेगा, तभी खीर डालोगी न ?' स्त्री ने कहा 'जी महाराज !' स्वामीजी बोले, 'मेरा भी यही उपदेश है। मन में जब तक चिन्ताओ का कूड़ा- कचरा और बुरे संस्करो का गोबर भरा है, तब तक उपदेशामृत का कोई लाभ न होगा। यदि उपदेशामृत पान करना है, तो प्रथम अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, कुसंस्कारो का त्याग करना चाहिए, तभी सच्चे सुख और आनन्द की प्राप्ति होगी।क्योंकि आपकी अच्छी सोच ही आपके कार्य को निर्धारित करती है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिये। जो प्राप्त है, पर्याप्त है।

व्यंग्य केसरी

झालमुड़ी क्यों खायी ?

गिरीश पंकज

नेताजी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक जगह रुक कर झालमुड़ी क्या खायी,विपक्ष को उनका खाना रास नहीं आया. एक बेचारा यह सोचकर पछताया कि यह आइडिया उसके नेता के दिमाग में क्यों नहीं आया.हम क्यों नाटक में पीछे रह गए.कई बार तो हमारे वो ज्यादा बड़े नौटंकीबाज होते हैं. उसकी सूची बड़ी लंबी है. लेकिन हम अपनी नौटंकी क्यों देखें. दूसरे की नौटंकी देखें. तो नेताजी ने झालमुड़ी खायी , तो उनकी पार्टी ने खुशी मनाई .

कार्यकर्ता रामस्वरूप ने फलस्वरूप से कहा, 'हमारे नेता वोट चोरी में बड़े माहिर हैं. '

फलस्वरूप भड़कते हुए बोला, ' क्या बकते हो ? आरोप लगा रहे हो ? '

रामस्वरूप मुस्कुराते हुए बोला, 'अरे भाई !कहने का तात्पर्य है कि हमारे नेता दिल चोरी करने में माहिर हैं.दिल चोरी करते हैं, तो स्वाभाविक है कि एक नहीं कई वोट उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं. अब झालमुड़ी बेचने वाला तो यह सोचकर गदगद हो गया कि देश का इतना बड़ा नेता हमारी छोटी-सी दुकान में आकर झलमुड़ी खाए तो मैं अब उनको ही वोट दूंगा. मेरी जोरू भी वोट देगी. माता-पिता भी. ' फलस्वरूप ने कहा, 'जे बात तो है.राजनीति में हथकंडे बहुत जरूरी हैं.कभी कोई नेता पान दुकान पर रुक जाता है, कभी कोई चाट के ठेले पर खड़ा जाता है,कभी कोई सब्जी भाजी खरीदने लगता है. यह देखकर भोली-भाली जनता भावुक हो जाती है. अपने आप को धन्य समझने लगती है. जबकि इसमें धन्य होने जैसी कोई बात नहीं. लेकिन वह धन्य होती रहती है. इसका फायदा पार्टी को मिल जाता है. इसलिए जब-जब चुनाव आता है, बहुत सारी नेता नारायण से नर बन जाते हैं. कोई खेत के भीतर घुस जाएगा और हल चलाने लगेगा,कोई लपक का ट्रैक्टर पर बैठ जाएगा. एक नेता तो गाड़ी का पंचर बनाने लगा था. मतदाता को लुभाने के लिए जब तक हथकंडे नहीं करेंगे तो जनता का दिल कैसे जीतेंगे.' रामस्वरूप ने कहा, ' इसलिए हमारे नेता अगर झालमुड़ी खाने चले गए तो कोई गलत नहीं किया. इधर उन्होंने झालमुड़ी खाई, उधर बहुतों की मूड़ी गर्म हो गई. कोई कह रहा है, देखो, कैमरा यहां पर था, वहां फिट था. अरे भैया, बड़ा नेता है तो उसके साथ तो कैमरे चलेंगे ही,सुरक्षा कर्मी भी रहेंगे. छुटभैये नेताओं के पीछे-पीछे भी कैमरे चलते हैं. '

फलस्वरूप ने कहा, 'लेकिन आलोचना करने वालों को कौन समझाए! '

रामस्वरूप मुस्कुराते हुए बोला, 'बेचारे! विपक्षी होने का धर्म निभा रहे हैं. नेता जी की तारीफ थोड़ी न करेंगे कि आप धन्य हैं. 'फलस्वरूप हँस पड़ा, 'तेरी बात में दम है यार! वैसे हमारे नेता जी की हर एक्टिविटी वायरल हो जाती है.अब झालमुड़ी भी वायरल हो गई.पता चला है कि झालमुड़ी वाले का माल अब खूब बिक रहा है. बंदा दोहरी कमाई भी कर रहा है. अब अब अपने इलाके का हीरो है. उसके साथ जो भी सेल्फी लेता है, उससे वह पैसे चार्ज करने लगा है।

इतिहास

21 अप्रैल के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ दर्ज हैं। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। वहीं, 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह 'आर्यभट्ट' लॉन्च किया। इसके अलावा, 1990 में प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर एर्टे का निधन हुआ। 21 अप्रैल की अन्य प्रमुख घटनाएं:

1930: प्रसिद्ध दांडी मार्च का समापन हुआ। 1966: मिहिर सेन ने पनामा नहर में तैराकी का कीर्तिमान बनाया। 1996: अमेरिकी गायक प्रिंस का 57 वर्ष की आयु में निधन हुआ (2016 के संदर्भ में)।

1987: श्रीलंका के कोलंबो में तमिल बम हमले में 115 लोग मारे गए। 753 ईसा पूर्व: रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार, रोमुलस और रेमस ने रोम की स्थापना की। राजस्थान के संदर्भ में: 30 मार्च 1949: राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन राजस्थान राज्य का गठन हुआ था।

भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ हरे निशान में बंद, सेंसेक्स में 753 अंकों की बढ़त

मुंबई । पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के चलते वैश्विक बाजार से मिले-जुले संकेतों के बीच मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूत बढ़त देखी गई, और प्रमुख बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद हुए। और इसतरह सेंसेक्स और निफ्टी50 ने लगातार तीसरे सत्र में अपनी बढ़त जारी रखी, क्योंकि निवेशक अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर सतर्क रूप से आशावादी बने रहे।

बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 753.03 अंकों यानी 0.96 प्रतिशत की बढ़त के साथ 79,273.33 पर था, तो वहीं एनएसई निफ्टी50 211.75 (0.87 प्रतिशत) की उछाल के साथ 24,576.60 पर ट्रेड करता नजर आया।

दिन के कारोबार में सेंसेक्स 78,617.16 पर खुलकर करीब 750 अंकों की बढ़त के साथ 79,367.08 का इंट्रा-डे हाई बनाया, जबकि निफ्टी50 24,374.55 पर खुलकर 227 अंकों की उछाल के साथ 24,601.70 का दिन का उच्चतम स्तर छुआ।

इस दौरान, बैंक निफ्टी इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1.39 प्रतिशत की बढ़त हासिल की। वहीं व्यापक बाजारों में निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.49 प्रतिशत तो निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.88 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

सेक्टरवार देखें तो निफ्टी रियल्टी में 2.14 प्रतिशत, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.50 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.01 प्रतिशत, निफ्टी मीडिया में 97 प्रतिशत और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.79 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और ये सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर रहे। इसके अलावा, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल में भी तेजी देखने को मिली। जबकि निफ्टी फार्मा का प्रदर्शन खराब रहा।

निफ्टी 50 पैक में नेस्ले इंडिया, एचयूएल, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इटरनल, आईटीसी, एक्सिस बैंक, अदाणी पोर्ट्स, विप्रो और टीसीएस के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। इसके विपरीत एसबीआई लाइफ, बीईएल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज, टाइटन, रिलायंस और एनटीपीसी के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली।

पीएलआईएसएफपीआई से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्षमता बढ़ी और रोजगार के अधिक अवसर पैदा हुए : केंद्र

नई दिल्ली। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री (पीएलआईएसएफपीआई) से देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्षमता में वृद्धि हुई है और साथ ही रोजगार एवं निर्यात को बढ़ावा मिला है। यह जानकारी सरकार की ओर से मंगलवार को दी गई।

केंद्र ने आधिकारिक बयान में कहा कि इस स्कीम के कारण फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन क्षमता में 34 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। पीएलआईएसएफपीआई के तहत लाभार्थी कंपनियों को 2,162.55 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

इस स्कीम के तहत सरकार ने 165 आवेदनों को मंजूरी दी है और इसने 9,207 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। इससे करीब 3.39 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं जो कि निर्धारित लक्ष्य 2.5 लाख से काफी अधिक है।

केंद्र ने बताया कि पीएलआईएसएफपीआई से एमएसएमई को काफी सपोर्ट मिला है और 165 में से 69 आवेदक एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) थे।

इसके अतिरिक्त, मुख्य अनुमोदित आवेदकों से जुड़ी 40 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थीं, जो कि एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जो मूल्य श्रृंखला में उनके एकीकरण को दर्शाती हैं।

केंद्र ने बताया कि 20 पात्र एमएसएमई को 13.26 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया गया है। साथ ही कहा कि 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर वित्त वर्ष 2026-27 के बीच लागू की गई पीएलआईएसएफपीआई स्कीम का लक्ष्य 33,494 करोड़ रुपए के प्रोसेस्ड फूड का उत्पादन करना है।

हाल के वर्षों में भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिसके तहत सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) 2014-15 में 1.34 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 2.24 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जैसा कि पहले संशोधित अनुमानों में बताया गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद, 2027 में 6.6 प्रतिशत रह सकती है विकास दरः यूएन रिपोर्ट

नई दिल्ली । भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है और 2027 में यह दर 6.6 प्रतिशत रह सकती है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दी गई।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में 2025 में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2024 में यह दर 5.2 प्रतिशत थी, और यह वृद्धि मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.4 प्रतिशत की मजबूत विकास दर से बढ़ने के कारण थी।

रिपोर्ट में कहा गया कि मजबूत ग्रामीण खपत, जीएसटी में कटौती, अमेरिकी टैरिफ से पहले एक्सपोर्ट फ्रंट लोडिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रिपोर्ट के आगे कहा गया कि अगस्त 2025 में अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लागू किए जाने के बाद यूएस को निर्यात में 25 प्रतिशत की गिरावट के चलते, वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में नरमी आई।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, भारत में मुद्रास्फीति 2026 में 4.4 प्रतिशत और 2027 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि व्यापारिक तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विकासशील एशियाई और प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में गिरावट आई है, जबकि 2024 में इसमें 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वैश्विक प्रवाह में 14 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, इस क्षेत्र में एफडीआई 2025 में 2 प्रतिशत तक गिर गया है।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, 'एशिया-प्रशांत क्षेत्र में, पहली तीन तिमाहियों में सबसे अधिक ग्रीनफील्ड एफडीआई आकर्षित करने वाले देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और कजाकिस्तान थे।

जिन्होंने क्रमशः 50 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर और 21 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की।

रिपोर्ट में भारत की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना की सराहना की गई है, जो सौर फोटोवोल्टिक, बैटरी और हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देकर हरित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली व्यापक आर्थिक नीति का प्रमाण है।

वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता से सोने और चांदी में गिरावट

मुंबई । भारत में मंगलवार को सोने और चांदी में गिरावट देखी गई। शुरुआती सत्र में दोनों कीमती धातु 0.68 प्रतिशत तक की गिरावट के साथ कारोबार कर रही थीं।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह 10:27 पर सोने के 5 जून 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.16 प्रतिशत या 243 रुपए कम होकर 1,53,700 रुपए पर था। अब तक के कारोबार में सोने ने 1,53,675 रुपए का न्यूनतम स्तर और 1,53,922 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है।

चांदी का 5 मई 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 0.70 प्रतिशत या 1,776 रुपए की कमजोरी के साथ 2,50,769 रुपए पर था। अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,50,210 रुपए का न्यूनतम स्तर और 2,51,222 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। सोना 0.43 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,807 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78.885 डॉलर प्रति औंस पर था।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटी एनालिस्ट मानव मोदी ने कहा कि अमेरिका-ईरान युद्धविराम और आगामी मैक्रो घटनाओं को लेकर अनिश्चितता के कारण बाजार में सतर्कता का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई।

उन्होंने आगे कहा कि इस सप्ताह युद्धविराम समाप्त होने से पहले नई शांति वार्ता हो पाएगी या नहीं, इस बात को लेकर बाजार में अनिश्चितता बनी रही। दोनों पक्षों से मिल रहे विरोधाभासी संकेतों ने अस्थिरता को और बढ़ा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए पाकिस्तान जाएगा, वहीं ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया कि जब तक अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी, वार्ता की संभावना कम है।

हालांकि, कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि तेहरान क्षेत्रीय मध्यस्थों के माध्यम से वार्ता में भाग ले सकता है। हाल ही में हुई सैन्य कार्रवाइयों, जिनमें अमेरिका द्वारा ईरान के झंडे वाले एक जहाज को जब्त करना भी शामिल है, ने भू-राजनीतिक जोखिमों को और भी बढ़ा दिया है।

सोने और चांदी में गिरावट की एक वजह डॉलर इंडेक्स को माना जा रहा है, जो कि मजबूत होकर 97.94 पर पहुंच गया है।

आमतौर पर जब भी डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है, तो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिलती है।

टिम कुक के बाद जॉन टर्नस के नेतृत्व में एप्पल की भारत में ग्रोथ की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद

नई दिल्ली। एप्पल के सीईओ टिम कुक, जो सितंबर में पद छोड़ने वाले हैं, अपने पीछे न सिर्फ 4 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी, बल्कि भारत में एप्पल की एक मजबूत और नई पहचान भी छोड़कर जा रहे हैं। वहीं, अब उनके उत्तराधिकारी जॉन टर्नस से उम्मीद की जा रही है कि वे इस सफर को आगे बढ़ाएंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि टर्नस के नेतृत्व में भारत में एप्पल की रणनीति और तेज हो सकती है। भारत अब कंपनी के लिए न सिर्फ एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, बल्कि एक अहम उपभोक्ता बाजार भी बन चुका है।

विशेषज्ञों के अनुसार, टिम कुक के नेतृत्व में भारत एप्पल के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक बन गया है। इसमें उत्पादन, रिटेल विस्तार और तेजी से बढ़ता यूजर बेस शामिल है।

उनका कहना है कि भारत आगे भी एक बड़े उत्पादन केंद्र के रूप में और एक तेजी से बढ़ते बाजार के रूप में एप्पल के लिए दोहरी भूमिका निभाएगा, जो कंपनी के वैश्विक विस्तार के अगले चरण को तय करेगा।

काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक ने कहा कि कुक ने भारत की क्षमता को पहचानने और उसे एप्पल की लंबी रणनीति के केंद्र में लाने में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने बताया कि कुक ने न सिर्फ भारत में मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल को बढ़ावा दिया, बल्कि डेवलपर्स और यूजर्स के साथ मजबूत जुड़ाव भी बनाया, जिससे स्थानीय बाजार में एप्पल की पकड़ मजबूत हुई।

पाठक ने यह भी कहा कि टर्नस को अब इस मजबूत नींव पर आगे काम करना होगा, खासकर भारत की लंबी अवधि की विकास संभावनाओं को देखते हुए। उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और नेतृत्व शैली भारत के युवा और महत्वाकांक्षी यूजर्स को पसंद आ सकती है।

साइबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) के वाइस प्रेसिडेंट प्रभु राम ने कहा कि भारत अब एप्पल की वैश्विक सप्लाई चेन रणनीति में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि अब एप्पल अपने करीब एक-चौथाई आईफोन भारत में असेंबल करता है, जिससे भविष्य में कंपनी की ग्रोथ में भारत की भूमिका और बढ़ेगी, जैसे पहले चीन की थी।राम ने यह भी कहा कि कुक के कार्यकाल की खासियत उनकी मजबूत कार्यशैली और बदलते हालात के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रही। उन्होंने खासकर चीन पर निर्भरता कम करने और भारत व वियतनाम जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर ध्यान दिया।पद छोड़ने की घोषणा करते हुए कुक, जो 2011 से एप्पल का नेतृत्व कर रहे हैं, ने कहा, 'एप्पल का सीईओ होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है।

कंपनी के अनुसार, कुक के कार्यकाल में एप्पल का मार्केट कैप करीब 350 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जबकि कंपनी की सालाना आय लगभग चार गुना बढ़कर 416 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई।

भारत में वित्त वर्ष 2026 में दोपहिया वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड 22 मिलियन तक पहुंच गईः रिपोर्ट

नई दिल्ली। भारत में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने वित्त वर्ष 2026 में नया रिकॉर्ड बनाया है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू थोक बिक्री (व्होलसेल) लगभग 2.2 करोड़ (22 मिलियन) यूनिट तक पहुंच गई।

आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 में थोक बिक्री में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि रिटेल बिक्री साल-दर-साल आधार पर 28.7 प्रतिशत बढ़ी। पूरे वित्त वर्ष में दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री लगभग 11 प्रतिशत बढ़ी।

रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री की वृद्धि दर घटकर 3-5 प्रतिशत रह सकती है। इसका कारण पिछले साल का उच्च आधार और अल नीनो के चलते कमजोर मानसून की संभावना है, जिससे ग्रामीण मांग पर असर पड़ सकता है।

हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी में सुधार और पुराने वाहनों को बदलने की बढ़ती मांग से बाजार को समर्थन मिलता रहेगा।

वित्त वर्ष 2026 में घरेलू थोक बिक्री में साल-दर-साल 10.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जीएसटी सुधारों के चलते तीसरी और चौथी तिमाही में बिक्री को बढ़ावा मिला। जहां पहली छमाही में करीब 1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि थी, वहीं दूसरी छमाही में यह बढ़कर 20.3 प्रतिशत हो गई।

रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 में रिटेल बिक्री 28.7 प्रतिशत बढ़ी और पूरे वित्त वर्ष 2026 में यह करीब 13 प्रतिशत रही।

इसमें कहा गया है कि इस बढ़ोतरी के पीछे जीएसटी सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रवाह में सुधार और बेहतर आर्थिक माहौल (जैसे रेपो रेट में कटौती और आयकर में राहत) जैसे कदम रहे, जिनसे उपभोक्ता मांग मजबूत हुई। इसके अलावा, कंपनियों द्वारा एंट्री-लेवल और प्रीमियम दोनों तरह के ग्राहकों के लिए नए-नए मॉडल लॉन्च करने से भी बिक्री को बढ़ावा मिला।

वित्त वर्ष 26 में ओबेरॉय रियल्टी की बिक्री 25 प्रतिशत घटी, चौथी तिमाही में बुकिंग में आया उछाल

मुंबई । ओबेरॉय रियल्टी ने वित्त वर्ष 2026 में बेची गई इकाइयों की संख्या में 24.86 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, जबकि कंपनी ने प्रीमियम आवास की मजबूत मांग के कारण तिमाही बुकिंग में तेज वृद्धि दर्ज की है।

ओबेरॉय रियल्टी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वित्त वर्ष के दौरान बुक की गई इकाइयों की कुल संख्या घटकर 698 रह गई, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 929 इकाइयां थी।

कंपनी ने अपनी फाइलिंग में यह भी बताया कि वर्ष के दौरान बुक किया गया कुल कारपेट एरिया भी 10.61 प्रतिशत घटकर 11,47,557 वर्ग फुट रह गया। वार्षिक बिक्री मात्रा में गिरावट के बावजूद, कंपनी ने बुकिंग मूल्य में मामूली 3.14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2026 में 5,447 करोड़ रुपए रही।

यह दिखाता है कि इकाइयों की बिक्री में गिरावट के बावजूद उच्च मूल्य वाली संपत्तियों की मांग अधिक बनी रही।

इसके विपरीत, वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। कुल बुकिंग मूल्य लगभग दोगुना होकर 1,673 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 853 करोड़ रुपए से 96.13 प्रतिशत अधिक है।

इस तिमाही में बुक की गई इकाइयों की संख्या पिछले वर्ष की 78 इकाइयों से बढ़कर 229 हो गई। फाइलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में बुक किया गया कारपेट एरिया पिछले वर्ष की तुलना में 160.37 प्रतिशत बढ़कर 3,57,552 वर्ग फुट हो गया।

तिमाही दर तिमाही आधार पर भी कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें बुकिंग मूल्य में 100.11 प्रतिशत की वृद्धि और बुक की गई इकाइयों में 76.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

रियल एस्टेट डेवलपर ने अपनी फाइलिंग में बताया कि बुक किए गए कारपेट एरिया में पिछली तिमाही की तुलना में 92.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विकास ओबेरॉय के नेतृत्व वाली ओबेरॉय रियल्टी को रियल एस्टेट क्षेत्र में चार दशकों से अधिक का अनुभव है ।

सिर्फ गर्मियों में मिलती है यह गोल-मटोल सब्जी, इसमें कूट-कूटकर भरे विटामिन और मिनरल्स

गर्मियों में खानपान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, ताकि सेहत ठीक बनी रहे। इस मौसम में कई ऐसी सब्जियां मिलती हैं, जिनका सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इन्हीं में से एक सब्जी टिंडा है, जिसे अंग्रेजी में एप्पल गार्ड कहा जाता है। यह गोल-मटोल सब्जी पोषण का खजाना है और खासतौर पर गर्मियों में शरीर को फिट और हाइड्रेट रखने में बेहद फायदेमंद होती है। इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है, इसलिए यह तेज गर्मी में शरीर को संतुलित रखने में मदद करती है। गर्मियों की इस सब्जी का सेवन करेंगे, तो गजब के फायदे मिल सकते हैं।

गाजियाबाद की डाइटिशियन रंजना सिंह के मुताबिक, टिंडा में पानी की अच्छी मात्रा होती है। गर्मियों में शरीर से पसीने के जरिए काफी पानी निकल जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में टिंडा का सेवन शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और आपको दिनभर तरोताजा बनाए रखता है। यह शरीर के तापमान को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, जिससे लू लगने का खतरा कम हो जाता है।

पोषक तत्वों की बात करें, तो टिंडा विटामिन ष्ट, विटामिन ८, आयरन, पोटैशियम और फाइबर से भरपूर होती है। विटामिन ष्ट इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, जबकि विटामिन८ आंखों की रोशनी और त्वचा के लिए फायदेमंद है। पोटैशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में सहायक होता है और फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है।

एक्सपर्ट की मानें, तो पाचन तंत्र के लिए टिंडा किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों की सफाई करता है और कब्ज, गैस व अपच जैसी समस्याओं को दूर रखने में मदद करता है। यह हल्की और जल्दी पचने वाली सब्जी है, इसलिए जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, उनके लिए यह बेहद लाभकारी मानी जाती है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए भी यह एक सुरक्षित विकल्प है।

वजन कम करने की चाह रखने वालों के लिए भी टिंडा एक बेहतरीन विकल्प है।

भारत में श्रमिकों के आंदोलन पर कानून क्या कहता है, कब यह गैरकानूनी हो जाता है

नोएडा में अप्रैल के दूसरे हफ्ते में श्रमिक आंदोलन हुआ, जो वेतन वृद्धि और सुविधाओं की मांग से शुरू होकर हिंसक हो गया। इसी वजह से इसे गैरकानूनी कहा गया। जानते हैं कि भारत में श्रमिकों के आंदोलन, प्रदर्शन और हड़ताल को लेकर कानून क्या कहता है। क्या भारत में कानून श्रमिकों को आंदोलन-प्रदर्शन करने की इजाजत देते हैं और उनके साथ क्या शर्तें होती हैं।

वैसे आपको बता दें कि भारत में श्रमिकों के आंदोलन, प्रदर्शन और हड़ताल पर कानून पूरी तरह प्रतिबंधात्मक नहीं है, लेकिन इसके साथ कई शर्तें और कंडीशन जरूर जुड़ी हैं। आंदोलन और प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन नियंत्रित तौर पर।

भारतीय संविधान बेशक मजदूरों और औद्योगिक श्रमिकों को आंदोलन, प्रदर्शन और हड़ताल की इजाजत देता है। संविधान में उसका प्रावधान भी है।

भारतीय संविधान के तहत श्रमिकों को ये अधिकार हैं:

अनुच्छेद 19(1)(ड्ड) - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19(1)(ड्ड) - शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार

अनुच्छेद 19(1)(ष) - संघ और यूनियन बनाने का अधिकार

मतलब यह है कि श्रमिक यूनियन बना सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांगें रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हड़ताल को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। इस बात को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है।

क्या भारत का कानून श्रमिकों को हड़ताल करने की इजाजत देता है

इंडस्ट्रियल विवाद एक्ट, 1947 हड़ताल और तालाबंदी की इजाजत तो देता है, लेकिन इसे कई शर्तों के साथ नियंत्रित भी करता है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे बिजली, रेलवे और पानी में हड़ताल से 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। बिना इसके हड़ताल नहीं कर सकते। जब विवाद सुलह प्रक्रिया में हो, तो हड़ताल नहीं कर सकते। अगर कोई मामला लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में हो, तो ऐसे में भी हड़ताल नहीं कर सकते। नियम तोड़ने पर हड़ताल गैरकानूनी मानी जाती है।

ट्रेड यूनियन कानून क्या कहता है

ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 कहता है कि श्रमिकों को यूनियन बनाने और रजिस्टर कराने का अधिकार है। यूनियन को कुछ कानूनी सुरक्षा भी मिलती है। लेकिन वर्ष 2020 में इन कानूनों में कुछ सुधार भी हुए हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 नए श्रम कानूनों में कुछ प्रावधान करता है:

- 300 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में छंटनी या बंद करने के लिए सरकारी अनुमति
- हड़ताल के लिए सभी सेक्टर में 14 दिन का नोटिस अनिवार्य
- नोटिस दिए बिना हड़ताल अवैध मानी जाएगी

क्या प्रदर्शन पर भी नियम हैं?

हां, केवल हड़ताल ही नहीं, प्रदर्शन पर भी कानून लागू होते हैं। सेक्शन 144 क्रिमिनल पीनल कोड लागू होने पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। पुलिस से अनुमति लेना जरूरी होता है। हिंसा, तोड़फोड़, रास्ता जाम करना गैरकानूनी हो सकता है।

इन सबको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या रूल देता रहा है

भारत की अदालतों ने साफ किया है कि हड़ताल बेशक कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। यूनियन बनाना मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल करना नहीं।

अगर श्रमिकों के आंदोलन के दौरान हिंसा और बवाल शुरू हो जाता है, तो फिर इसे गैरकानूनी करार दिया जाता है और इसे अपराध की श्रेणी में ले आया जाता है।

कब कोई आंदोलन 'गैरकानूनी' हो जाता है?

अगर श्रमिक बिना नोटिस हड़ताल करें, हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, कोर्ट और सरकार के आदेश का उल्लंघन करें - अगर ऐसा होता है, तो आंदोलन गैरकानूनी और दंडनीय अपराध हो जाता है।

क्या यह सही है कि कानून तो बने हुए हैं, लेकिन सिस्टम इन्हें कमजोर कर सकता है या करता रहा है? बिल्कुल, यह भी सच है। कागज पर श्रमिकों को अधिकार हैं, लेकिन हकीकत में प्रशासन का रुख और सिस्टम उनके आंदोलन को अक्सर कमजोर करने का काम ज्यादा करते रहे हैं।

सरकार और कंपनियां आवश्यक सेवाओं का हवाला देकर उनके आंदोलन पर रोक लगा सकती हैं। पुलिस से अनुमति लेने की प्रणाली आंदोलन को सीमित करती है।

चांद की ग्रेविटी में आग बुझती नहीं, बल्कि और भड़कती है: नासा करने जा रहा बड़ा टेस्ट

चांद की सतह पर इंसानी बस्तियां बसाने का सपना अब हकीकत बनने की ओर है। लेकिन इस सपने के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी है, जिससे नासा के वैज्ञानिक सबसे ज्यादा डरते हैं। वह चुनौती है—आग। पृथ्वी पर आग पर काबू पाना आसान होता है, लेकिन अंतरिक्ष और चांद की परिस्थितियों में यह किसी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। हाल ही में नासा के ग्लेन रिसर्च सेंटर, जॉनसन स्पेस सेंटर और केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नए मिशन का खाका तैयार किया है। इस मिशन का नाम 'फ्लेमेबिलिटी ऑफ मैटेरियल्स ऑन द मून' यानी एफएम है।

इस प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिक चांद की सतह पर विभिन्न चीजों के जलने की क्षमता का परीक्षण करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि चांद पर आग की लपटें पृथ्वी की तुलना में बिल्कुल अलग तरह से काम करेंगी। भविष्य में जब इंसान चांद पर लंबे समय तक रहेगा, तो वहां के वातावरण में आग लगने की स्थिति से निपटना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।

चांद पर आग इतनी खतरनाक क्यों है?

पृथ्वी पर जब आग जलती है, तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। गर्म गैसें हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती हैं। इस वजह से आग के निचले हिस्से में ताजी और ठंडी ऑक्सीजन पहुंचती रहती है।

कभी-कभी हवा का यह बहाव इतना तेज होता है कि वह कम जलने वाली चीजों की आग को खुद ही बुझा देता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में 'ब्लोऑफ' कहा जाता है।

लेकिन चांद पर मामला बिल्कुल उल्टा है। वहां पृथ्वी के मुकाबले ग्रेविटी बहुत कम है। कम ग्रेविटी की वजह से वहां गैसों का बहाव बहुत धीमा होता है। इसका मतलब यह है कि आग को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहेगी, लेकिन हवा की रफ्तार इतनी नहीं होगी कि वह आग को बुझा सके। सरल शब्दों में कहें तो जो चीजें पृथ्वी पर आसानी से नहीं जलतीं, वे चांद पर लंबे समय तक धधक सकती हैं।

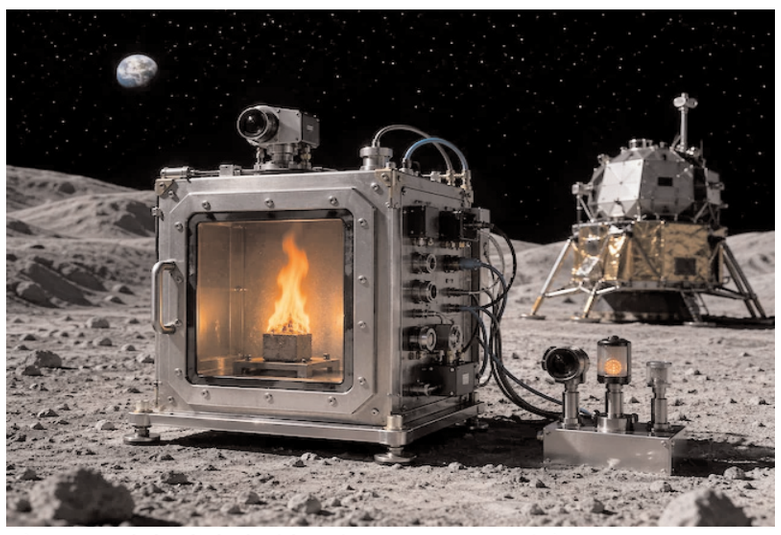

अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उनके रहने की जगह यानी हैबिटेट में आग लगना सबसे भयानक सपना हो सकता है। इसलिए नासा वहां स्थायी बस्ती बनाने से पहले ही इस खतरे को पूरी तरह समझ लेना चाहता है।

क्या पुराना टेस्टिंग सिस्टम फेल हो रहा है?

नासा पिछले कई दशकों से अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले सामान की जांच के लिए 'NASA-STD-6001B' स्टैंडर्ड का उपयोग कर रहा है।

इस टेस्ट में किसी भी चीज को वर्टिकल यानी सीधा खड़ा करके उसके निचले हिस्से में आग लगाई जाती है। अगर वह चीज 6 इंच से ज्यादा जल जाती है या जलते हुए टुकड़े नीचे गिराती है, तो उसे फेल मान लिया जाता है।

सुनने में यह तरीका सही लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ी खामी है। यह पूरा टेस्ट पृथ्वी की ग्रेविटी में किया जाता है।

अंतरिक्ष और चांद का वातावरण पृथ्वी से बहुत अलग है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (माइक्रोग्रैविटी) वाले इलाकों में 'ऊपर' या 'नीचे' जैसा कुछ नहीं होता।

वहां आग की लपटें ऊपर की ओर नहीं उठतीं, बल्कि वे एक गोल गोले या 'ब्लॉब' की तरह फैलती हैं। ये लपटें बहुत धीरे-धीरे बाहर की ओर बढ़ती हैं और स्टेशन के वेंटिलेशन सिस्टम से मिलने वाली ऑक्सीजन पर जिंदा रहती हैं।

अगर वहां वेंटिलेशन बंद भी कर दिया जाए, तो भी खतरा टलता नहीं है। बिना हवा के सामान धीरे-धीरे सुलगता रहता है और जैसे ही दोबारा पंखे चलते हैं, वह फिर से भड़क उठता है।

सफायर टेस्ट से क्या मिला नया डेटा?

नासा ने पहले भी अंतरिक्ष में आग के व्यवहार को समझने के लिए 'स्पेसक्राफ्ट फायर सेफ्टी' यानी सफायर टेस्ट किए हैं। ये प्रयोग मानवरहित सिग्नस कार्गो कैप्सूल के अंदर किए गए थे।

रात में क्यों हो रही जानलेवा गर्मी, दिन ढलने के बाद भी राहत नहीं, शरीर पर खतरनाक असर की वजह

मार्च और अप्रैल के शुरुआती दिनों तक मौसम की गजब आंख-मिचौली चलती रही। अब गर्मी का कहर बढ़ रहा है। दिन के समय झुलसाने वाली धूप से गर्मी का असर अब सूरज ढलने के बाद भी बना रह रहा है। आलम यह है कि आधी रात के समय तक दीवारें गर्म रह रही हैं। पंखे और कूलर का असर खत्म हो रहा है। रात के समय मिलने वाली राहत अब गायब होती जा रही है, क्योंकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचने लगा है। वैज्ञानिक इसे 'वार्म नाइट्स' कहते हैं। लोग देर शाम भी घर से लेकर सार्वजनिक जगहों पर नल से नहाते देखे जा रहे हैं। देश का 55 प्रतिशत हिस्सा हाई हीट रिस्क जोन में आ चुका है। इसकी वजह क्या है, आइए समझते हैं। देश में बढ़ते गर्मी संकट के बीच इन 'गर्म रातों' को अब भी नजरअंदाज किया जा रहा है। सुबह से दोपहर और शाम तक की चर्चा तो हो ही रही है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन और स्थानीय शहरीकरण के दोहरे प्रभाव के कारण भारत में रातें लगातार गर्म हो रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में असामान्य रूप से गर्म रातों और सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान का पूर्वानुमान जताया है।

क्या होती है वार्म नाइट यानी 'गर्म रात'?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले कुछ सालों में रात के बढ़ते तापमान की समस्या गंभीर हुई है, लेकिन दिन की गर्मी की तुलना में इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। ढ्ढरूष्ठ के अनुसार, जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है, तो उसे 'गर्म रात' कहा जाता है। यदि यह अंतर 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए, तो इसे 'बेहद गर्म रात' माना जाता है। अक्सर यह स्थिति तब बनती है, जब दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है।

बढ़ती गर्मी को लेकर प्रमुख आंकड़े और रिसर्च हुए हैं। साइंस डायरेक्ट 2025 की रिपोर्ट बताती है कि 1980 से 2020 के बीच गर्म रातों की संख्या में प्रति दशक 2 से 8 दिनों की वृद्धि हुई है। वहीं काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर (CEEW) की रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में यह प्रभाव अधिक है। 2012-2022 के बीच मुंबई में 15, बेंगलुरु में 11 और दिल्ली में 6 अतिरिक्त गर्म रातें दर्ज की गईं। यहां एल नीनो प्रभाव भी अहम है। 2026 एक एल नीनो वर्ष होने के कारण 2027 की गर्मी और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

इन गर्म रातों यानी वार्म नाइट्स की बात करें, तो पिछले एक दशक में भारत के शहरों में इनमें 32 प्रतिशत का इजाफा हो चुका है। पिछले साल 2025 में ही फरवरी खत्म होते-होते रात का तापमान बढ़ गया था। अधिकतर जगहों पर 3 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। गर्मी के फैक्टर पर बात करें, तो भारत के 266 जिले बहुत गंभीर गर्मी की कैटेगरी में हैं। वहीं 151 जिले गंभीर और 201 जिले मध्यम कैटेगरी में आ गए हैं।

रातें गर्म होने के कारण क्या हैं?

रातों के गर्म होने के पीछे दुनिया में हो रहा जलवायु परिवर्तन और गर्म होते जा रहे शहरी इलाके ही मुख्य कारण हैं।

अश्वगंधा का इस्तेमाल कर रहे हैं? FSSAI ने पत्तियों के उपयोग पर जताई आपत्ति, विशेषज्ञों ने बताया क्या है सुरक्षित

अश्वगंधा लंबे समय से भारत की वेलनेस परंपरा का अहम हिस्सा रहा है, जिसे तनाव कम करने और इम्युनिटी बढ़ाने के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) की एक एडवाइजरी के बाद इस लोकप्रिय जड़ी-बूटी के उपयोग को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।

अप्रैल 2026 में खाद्य नियामक ने एक निर्देश जारी कर अश्वगंधा की पत्तियों के किसी भी रूप में—

खाद्य उत्पादों, सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स में—उपयोग पर रोक लगा दी। यह स्पष्ट किया गया कि मौजूदा नियमों के तहत केवल इसकी जड़ (रूट) और उसके अर्क का ही सेवन अनुमत है।

क्या बदला है?

तकनीकी रूप से यह अश्वगंधा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यह तय करने का सख्त अनुपालन है कि पौधे का कौन-सा हिस्सा सुरक्षित और स्वीकृत है।

भारत के न्यूट्रास्यूटिकल दिशा-निर्देशों के अनुसार:

केवल अश्वगंधा की जड़ को सुरक्षित माना गया है

कुछ निर्माता पत्तियों के अर्क का उपयोग कर रहे थे, जो अनुमति सूची में नहीं है

नई एडवाइजरी में साफ कहा गया है:

पत्तियों का उपयोग खाद्य या स्वास्थ्य उत्पादों में नहीं किया जा सकता

केवल जड़ और उसके अर्क का निर्धारित सीमा में उपयोग किया जा सकता है

राज्यों को निगरानी और उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं

पत्तियों पर रोक क्यों?

यह फैसला मुख्य रूप से सुरक्षा चिंताओं और पर्याप्त वैज्ञानिक डेटा की कमी के कारण लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पत्तियों के अर्क से संभावित जोखिम हो सकते हैं,।

पहलगाम मुख्य आधार के रूप में, अमरनाथ यात्रा 2025 के आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा की अहम परीक्षा होगी

2026 की अमरनाथ यात्रा क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जा रही है, क्योंकि यह अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद हो रही है, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी और पिछले पर्यटन सीजन पर गहरा असर पड़ा था।

अमरनाथ यात्रा सुरक्षा की परीक्षा क्यों है

यह यात्रा अपने बड़े पैमाने और उच्च दृश्यता के कारण क्षेत्र की सबसे जटिल सुरक्षा चुनौतियों में से एक है।

पहलगाम (48 किमी) और बालटाल (14 किमी) दोनों मार्गों पर तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था

लागू है।

प्रशासन ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

नो-फ्लाइंग ज़ोन: यात्रा मार्गों पर ड्रोन और गुब्बारों सहित सभी हवाई उपकरणों पर प्रतिबंध।

अनिवार्य RFID: हर यात्री और वाहन को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के जरिए रियल-टाइम में ट्रैक किया जा रहा है।

हाई-टेक उपकरण: फेसियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS), 3ष्ठ रूट मैपिंग और जैमर का इस्तेमाल ढ्ढश्वष्ठ या स्नाइपर हमलों को रोकने के लिए किया जा रहा है।

करीब 500-580 कंपनियां अर्धसैनिक बलों (CAPF) की, साथ ही भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस, बेस कैंपों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात हैं।

पर्यटन और आर्थिक परीक्षा

इस यात्रा को अक्सर स्थानीय अर्थव्यवस्था की 'रीढ़' कहा जाता है, लेकिन फिलहाल यह पुनर्प्राप्ति और प्रतिबंध—दोहरी चुनौती का सामना कर रही है।

प्रशासन इस तीर्थयात्रा के जरिए 'सामान्य स्थिति की वापसी' दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर यात्रा सुरक्षित रूप से पूरी होती है, तो यह आम पर्यटकों को यह भरोसा दिलाने के लिए 'ब्रांड एंबेसडर' का काम करेगी कि कश्मीर सुरक्षित है।

यह यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये तक उत्पन्न कर सकती है।

प्रतिबंधों का प्रभाव

हालांकि सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, लेकिन कड़े इंतजाम सामान्य पर्यटन को प्रभावित कर सकते हैं:

यात्री काफिलों के लिए सड़क अवरोधों के कारण आम पर्यटकों को घंटों इंतजार करना पड़ सकता है।

महिला आरक्षण संशोधन बिल पास न होने पर भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने जताई निराशा

पटना। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास होने पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी बिहार के विकास की उम्मीद भी की है। आरा के एक कार्यक्रम में पहुंचीं अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा, 'काफी समय से देश की सभी महिलाएं इस बिल के पास होने का इंतजार कर रही थीं, लेकिन बिल पास नहीं हो सका। एक महिला होने के नाते मेरा मानना है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम से कम 33 फीसदी तो होनी ही चाहिए। खैर, अब देखना होगा कि कितना और लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर आम्रपाली दुबे का कहना है कि उनके ऊपर भी नीतीश कुमार की तरह बिहार के विकास की बड़ी जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार ने विकास की राह को करीब से देखा है और ऐसे में सम्राट चौधरी से भी बिहार को बहुत उम्मीदें हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वे बिहार के विकास के लिए काम करेंगे।' नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलवाई थी।

आम्रपाली दुबे मंगलवार को पटना स्थित 51 शक्तिपीठ मंदिरों में से एक बड़ी पटन देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं। माना जाता है कि इस मंदिर में मां सति की दाहिनी जांघ गिरी थी। मां पटन देवी को बिहार शहर की रक्षिका भी कहा जाता है।

मां पटन देवी के नाम पर ही पटना का नाम पड़ा था। मंदिर में मां के तीन सर्वशक्तिशाली रूपों की पूजा होती है, जिसमें मां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती गर्भगृह में विराजमान हैं। अभिनेत्री ने दर्शन के बाद की फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

शादी की सालगिरह से पहले यश कुमार ने दिया निधि झा को खास सरप्राइज, अभिनेत्री ने लिखा- 'हर जन्म में हम ही एक-दूसरे की जान खाएंगे'

मुंबई। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय कपल निधि झा और यश कुमार सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते है। दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ मजेदार वीडियो और साथ में बिताए पलों की झलक शेयर करते रहते हैं और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं।

मंगलवार को अबिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर यश कुमार के लिए एक खास पोस्ट किया। उन्होंने यश के लिए एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा।

दरअसल, निधि और यश ने 2 मई 2022 को भव्य तरीके से शादी की थी। अब उनकी शादी की सालगिरह नजदीक आ रही है, तो उससे पहले ही यश ने निधि को खास सरप्राइज दिया। इस तोहफे से

निधि काफी खुश नजर आ रही हैं।

निधि ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए पति यश कुमार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक प्यारी तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों साथ नजर आ रहे हैं। दिल की बात लिखते हुए उन्होंने लिखा, 'मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ख्वाहिशों को आप इतना तवज्जो देंगे। मैं तो बस एक छोटा सा सरप्राइज चाहती थी, लेकिन आपने हमारे एनिवर्सरी वीक को यादगार बना दिया। आप सच में मेरी सबसे बड़ी खुशी हैं। धन्यवाद आपका। अब हर जन्म से हम ही एक-दूसरे की जान खाएंगे।

अभिनेत्री की पोस्ट के उनके प्रशंसक काफी पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन पर सरप्राइज के बारे में पूछ रहे हैं। दरअसल, अभिनेत्री ने अपनी पोस्ट में सरप्राइज के बारे में जानकारी नहीं दी।

भोजपुरी सिनेमा में दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद किया जाता है और पावर कपल में गिना भी जाता है। उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर हो या असल जिंदगी में, हमेशा फैंस को पसंद आती है।

हालांकि, निधि यश की दूसरी पत्नी हैं। इससे पहले यश अभिनेत्री अंजना सिंह के साथ शादी के बंधन में थे। साल 2017 में आई फिल्म 'इंडिया वर्सेस पाकिस्तान' में एक साथ काम करने के दौरान यश कुमार और निधि झा एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। वहीं, पत्नी अंजना को तलाक देने के तुरंत बाद यश कुमार ने निधि झा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। साल 2022 में इन दोनों ने बड़ी धूमधाम से शादी रचाई थी।

अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने एआई और डीपफेक से उनकी पहचान के गलत इस्तेमाल पर लगाई रोक

नई दिल्ली। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कई कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को उनके नाम, चेहरा, आवाज और पहचान से जुड़ी किसी भी चीज का बिना अनुमति इस्तेमाल करने से रोक दिया है। यह आदेश खासतौर पर आज के दौर में तेजी से बढ़ रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस तुषार राव गेडेला की एकल पीठ ने की। अल्लू अर्जुन ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और कुछ अन्य संस्थाओं पर आरोप लगाया था कि वे उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी अनुमति के बिना उनके नाम से सामान बेचा जा रहा है और इंटरनेट पर गलत और भ्रामक कंटेंट फैलाया जा रहा है।

अल्लू अर्जुन ने याचिका में बताया कि कुछ लोग एआई तकनीक का इस्तेमाल कर उनकी आवाज की नकल कर रहे हैं और फेक कॉल जैसी चीजें तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा, कुछ जगहों पर उनकी छवि का उपयोग करके आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री भी बनाई जा रही थी। इस तरह की गतिविधियां उनके काम और छवि पर भी असर डाल रही हैं।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अल्लू अर्जुन देश के एक बड़े और सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने सालों की मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाई है और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें आइकन स्टार के नाम से जाना जाता है। कोर्ट ने उनके करियर का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने फिल्म 'विजेता' से बतौर बाल कलाकार शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दीं और 'पुष्पा: द राइज' और 'पुष्पा 2: द रूल' जैसी फिल्मों से उन्हें देश और दुनिया में बड़ी पहचान मिली। जस्टिस गेडेला ने कहा कि अल्लू अर्जुन की पहचान से जुड़ी हर चीज, जैसे उनका नाम, चेहरा, आवाज, बोलने का तरीका, डायलॉग, हावभाव और स्टाइल उनकी खास पहचान है और इसे बिना अनुमति इस्तेमाल करना गलत है।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अल्लू अर्जुन ने अपने नाम और ब्रांड से जुड़े कई ट्रेडमार्क रजिस्टर कराए हुए हैं।

एडीएचडी को कमजोरी नहीं, 'सुपर पावर' मानती हैं कुब्रा सैत, कहा- 'थेरेपी से खुद को समझने की मिली ताकत'

मुंबई। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोग खुलकर बात करने लगे हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसी स्थितियां हैं, जिनके बारे में लोग बोलने से हिचकते हैं। खासकर जब बात अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (एडीएचडी) की हो, तो अक्सर इसे सिर्फ एक परेशानी के रूप में देखा जाता है। इस कड़ी में अभिनेत्री कुब्रा सैत ने इस सोच को बदलने की कोशिश की है।

उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए अपने अनुभवों के बारे में बात की और इस स्थिति को अपनी 'सुपर पावर' बताया।

वीडियो में कुब्रा सैत कहती हैं, ''लंबे समय तक मैंने खुद को समझने की कोशिश की और इसके लिए थेरेपी का सहारा लिया। शुरुआत में मुझे अपने दिमाग को समझना मुश्किल लगता था, लेकिन धीरे-धीरे साफ समझ आने लगा कि मेरा सोचने का तरीका अलग है और

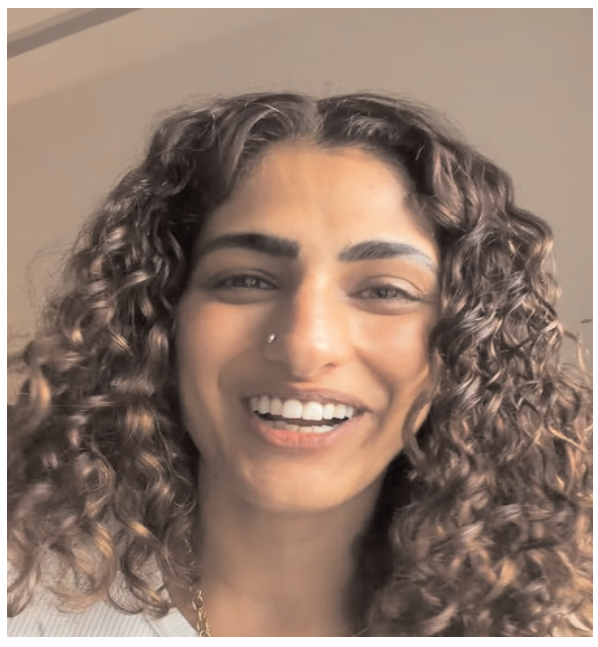

यही मेरी खासियत भी है।

उन्होंने वीडियो के कैप्शन में भी अपने दिल की बात लिखी। उन्होंने कहा, ''अब मुझे लगता है कि मेरा दिमाग पूरी तरह सक्रिय है और मैं इसे बेहतर तरीके से समझ पाई हूं। सालों की मेहनत, सोच-विचार और इलाज के बाद मुझे अपने भीतर की आवाज को समझने की ताकत मिली है। अब मैं पहले से ज्यादा खुश हूं और जिंदगी को लेकर नजरिया भी सकारात्मक हो गया है।

उन्होंने कहा, ''शायद पहले मैं अपने ही स्वभाव के खिलाफ चल रही थी, लेकिन अब मैंने अपने तरीके को अपनाना सीख लिया है।

कुब्रा ने अपने कैप्शन में लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ''मैं अकेली नहीं हूं और दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, जो इसी तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं। मेरी सभी से अपील है कि वे भी अपनी बात खुलकर रखें और अपने अनुभवों को छुपाने के बजाय स्वीकार करें।

उन्होंने बताया, ''एडीएचडी के साथ कुछ चुनौतियां जरूर आती हैं, जैसे एक जगह ध्यान टिकाना मुश्किल होना, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो यह आपकी ताकत भी बन सकता है। इस स्थिति में मैंने अपनी रचनात्मकता को बढ़ाया है और अलग तरीके से सोचने की क्षमता को भी विकसित किया है, जो अब मेरे काम में भी नजर आती है।

बता दें कि अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (एडीएचडी) एक ऐसी मानसिक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति का मन एक जगह टिक नहीं पाता। ऐसे लोगों को किसी एक काम पर लंबे समय तक ध्यान लगाना मुश्किल होता है, वे जल्दी-जल्दी ध्यान बदलते हैं, ज्यादा बेचैन रहते हैं, या बिना सोचे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। ज्यादातर लोग मजाक बनने के डर से इस पर खुलकर बात करने से बचते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, एडीएचडी में दिमाग अलग तरीके से काम करता है।

जहां एक तरफ ध्यान भटकने, बेचैनी और एक काम पर टिके रहने में दिक्कत होती है, वहीं दूसरी तरफ यही दिमाग बहुत तेज, क्रिएटिव और नए आइडिया सोचने वाला भी होता है। उनका दिमाग चीजों को अलग नजर से देखता है, जल्दी बोर हो जाता है, ऐसे में वे कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। यही आदत उन्हें क्रिएटिविटी में मदद कर सकती है।

सैयारा फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा पर टूटा दुखों का पहाड़, दादा के निधन से टूटीं अभिनेत्री

मुंबई। यश राज फिल्म्स की फिल्म 'सैयारा' से अपना डेब्यू करने वाली अनीत पड्डा एक बार फिर निर्देशक मोहित सूरी की अपकमिंग फिल्म 'सतरंगा' में अहान पांडे के साथ दिखने वाली हैं, लेकिन इसी बीच अभिनेत्री पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है क्योंकि जीवन के सबसे प्यारे इंसान ने उन्हें अलविदा कह दिया है। अनीत पड्डा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दादा जी के

निधन की जानकारी दी है, जो काफी समय से अल्जाइमर रोग से जूझ रहे थे। अभिनेत्री ने अपने दादा के हाथ की फोटो शेयर की है और अपने इमोशन को शब्दों के जरिए जाहिर किया। उन्होंने लिखा, 'मेरे जीवन का एकमात्र प्यार। आप मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन मक्खन (अनीत का निकनेम) को नहीं भूले। आपने प्यार को थामे रखा, भले ही आप यादों को थामे नहीं रख सके। मैं दोनों को थामे रहूंगी। मैं हमारे साथ बिताए सभी पलों को संजोकर रखूंगी। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगी। मैं आपके चुटकुले याद रखूंगी और जब भी मौका मिलेगा उन्हें दोहराऊंगी। मैं आपकी दयालुता और आपकी रोशनी को हर अंधेरे कमरे में ले जाऊंगी। मैं आपकी कहानियां याद रखूंगी और दुनिया को सुनाऊंगी। मैं आपके प्यार को थामे रहूंगी। आपने मुझे सबसे शुद्ध और सबसे निशर्त प्यार करना सिखाया।अनीत पड्डा ने लिखा, 'आज मैंने आकाश में सबसे चमकीला तारा देखा और मैं जान गई कि आप कहां गए। मैं आपसे प्यार करती हूं दादाजी और हमेशा अपनी सीमाओं से परे करती रहूंगी। अभिनेत्री के पोस्ट से साफ है कि वे अपने दादाजी के साथ कितना लगाव रखती थीं। बता दें कि सैयारा रिलीज के समय भी अभिनेत्री के दादाजी की तबीयत खराब होने के वजह से थिएटर नहीं आ पाए थे, लेकिन फोन में कुछ वीडियो को देखकर उन्होंने अनीत को पहचान लिया था ।

सेना प्रमुख का हवाई दौरा, भारत-अमेरिका रक्षा संबंध और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता पर जोर

वाशिंगटन। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने होनोलूलू में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल, जनरल रोनाल्ड पी. क्लार्क और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए साझा दृष्टिकोण आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

जब जनरल द्विवेदी हवाई स्थित यूएस मिलिट्री बेस पर पहुंचे, तो फोर्ट शैफ्टर में उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया और उन्होंने ओहू द्वीप का हवाई दौरा भी किया। भारतीय सेना के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय (एडीजीपीआई) ने एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी। बताया, 'जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीओएएस, को यूएस आर्मी पैसिफिक की अपनी मौजूदा यात्रा के दौरान, हवाई के फोर्ट शैफ्टर में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। उन्होंने अमेरिकी आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल, जनरल रोनाल्ड पी. क्लार्क और अन्य वरिष्ठों के साथ बातचीत की। इस दौरान भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग मजबूत करने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर जोर रहा। सीओएएस ने ओहू द्वीप का हवाई दौरा भी किया, जिससे उन्हें ट्रेनिंग इकोसिस्टम और बहु-क्षेत्रीय परिचालन तत्परता की जानकारी मिली।'

इस महीने की शुरुआत में, भारत और अमेरिका ने अपनी वायु सेनाओं के प्रमुखों के बीच हुई उच्च-स्तरीय बातचीत के दौरान अपनी रणनीतिक रक्षा साझेदारी की फिर से पुष्टि की; इस बातचीत का मुख्य एजेंडा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आपसी तालमेल, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय प्रतिरोधक क्षमता पर जोर देना था। यूएस वायु सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल केनेथ विल्सबैक ने 8 अप्रैल को भारतीय वायु सेना के प्रमुख, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह की आधिकारिक यात्रा की मेजबानी की थी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सिंह का जॉइंट बेस एनाकोस्टिया-बोलिंग में पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया गया और बाद में उन्होंने पेंटागन में वायु सेना के सचिव, ट्रॉय मिंक और विल्सबैक के साथ बैठक भी की। बातचीत के दौरान, यूएस वायु सेना के वरिष्ठ अफसरों ने बताया कि भारत के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को वाशिंगटन बहुत महत्व देता है; उन्होंने इसे 'एक स्वतंत्र, खुला, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र' सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। विल्सबैक ने समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ बहुपक्षीय अभ्यासों में भारत के नेतृत्व और भागीदारी की सराहना की, और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के सहयोग का विस्तार करना क्षेत्रीय प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की कुंजी होगी।

अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारत में कीमतें स्थिर

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। वहीं, कई देशों में ईंधन की कीमतों में 85 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है।

एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, कोटक द्वारा जारी आंकड़ों में भारत और अन्य विकसित व उभरते देशों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला है, जहां इस साल अब तक कई देशों में ईंधन की कीमतें काफी बढ़ी हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। डीजल की बात करें भू-राजनीतिक तनावों के चलते हाल के महीनों में कई देशों में इसकी कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। देशों के हिसाब से देखें तो, यूएई में डीजल की कीमतें करीब 85 प्रतिशत बढ़ीं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में 65 प्रतिशत और 62 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, कनाडा, पाकिस्तान, फ्रांस, श्रीलंका और ब्रिटेन में कीमतें 35 से 53 प्रतिशत तक बढ़ीं। इसके अलावा, चीन और ब्राजील जैसे देशों में बढ़ोतरी थोड़ी कम रही, जबकि रूस में डीजल की कीमतें केवल 1 प्रतिशत से थोड़ी ज्यादा बढ़ीं।

इसके विपरीत, भारत में डीजल की कीमत जनवरी के स्तर पर ही 87.6 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है, यानी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, भले ही अमेरिका-ईरान तनाव जारी है। पेट्रोल की कीमतों में भी ऐसा ही रुझान देखने को मिला। पड़ोसी पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा, यानी 44 प्रतिशत बढ़े। इसके बाद अमेरिका (42 प्रतिशत) और यूएई (36 प्रतिशत) का स्थान रहा। वहीं, कनाडा, श्रीलंका और चीन में पेट्रोल की कीमतें 34 प्रतिशत तक बढ़ीं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी हुई। कम बढ़ोतरी वाले देशों में ब्राजील और रूस शामिल हैं, जहां कीमतें क्रमश: 7 प्रतिशत और 1 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा बढ़ीं।

भारत में पेट्रोल की खुदरा कीमतें जनवरी के स्तर पर 94.7 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई हैं, यानी उपभोक्ताओं के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहना यह दिखाता है कि सरकारी नीतियों और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (ओएमसी) की कीमत निर्धारण व्यवस्था ने कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद की है। वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर नहीं पड़ा है।

जर्मनी के मोएर्स गुरुद्वारे में चुनावों को लेकर हिंसक झड़प, 11 लोग घायल

बर्लिन। जर्मन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जर्मनी के मोएर्स शहर के डुइसबर्ग इलाके में एक गुरुद्वारे के अंदर हिंसक झड़प होने से कम से कम 11 लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की और विशेष सामरिक इकाइयों को तैनात किया।

खबरों के मुताबिक, इस घटना में करीब 40 लोग शामिल थे और यह धार्मिक परिसर के अंदर तेजी से एक हिंसक झड़प में बदल गई।

सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वे गुरुद्वारे के अंदर के हैं, उनमें दो गुटों के सदस्यों को हिंसक झड़प करते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्टों से पता चलता है कि झड़प के दौरान चाकू और कृपाण जैसे धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। कुछ खबरों में यह भी कहा गया है कि परिसर के अंदर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया और एक हथियार से गोली भी चलाई गई।

जर्मन अखबार 'बिल्ड' ने बताया कि झड़प के सही कारण की जांच चल रही है, लेकिन शुरुआती नतीजों से पता चलता है कि यह हिंसा गुरुद्वारा प्रबंधन बोर्ड के नए चुनाव को लेकर हुए विवादों से जुड़ी हो सकती है। माना जा रहा है कि इन अंदरूनी मतभेदों में गुरुद्वारे के फंड पर नियंत्रण का मामला भी शामिल है, जिसमें विरोधी गुट कथित तौर पर अधिकार और वित्तीय प्रबंधन को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। 56 साल के एक चश्मदीद ने 'बिल्ड' को बताया कि यह जरूर पहले से प्लान किया गया होगा। सेवा शुरू होने से कुछ ही देर पहले, हमलावरों के पास अचानक पेपर स्प्रे आ गया और उन्होंने अपने विरोधियों पर स्प्रे कर दिया। फिर उनमें से एक ने पिस्तौल से गोली चलाई और मैंने चाकू भी देखे। चश्मदीद ने आगे बताया कि कुछ समय से तनाव बढ़ रहा था, जिसका मुख्य कारण प्रबंधन समिति के भीतर नेतृत्व और नियंत्रण से जुड़े मुद्दे थे। एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि हमले के दौरान गुरुद्वारे के अंदर अफरा-तफरी मच गई, जिससे कई लोगों को परिसर छोड़कर भागना पड़ा। चश्मदीद ने कहा कि नतीजे इससे भी ज्यादा बुरे हो सकते थे। शुक्र है कि किसी की जान खतरे में नहीं है। आपातकालीन सेवाओं ने मौके पर ही घायलों का इलाज किया, जबकि पुलिस ने पुष्टि की कि कम से कम एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। अपराध विभाग के जांचकर्ता फिलहाल घटनाक्रम का पता लगाने और हिंसा में शामिल सभी लोगों की पहचान करने पर काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है। हालांकि, शुरुआती फोरेंसिक नतीजों से पता चलता है कि यह एक 'ब्लैंक-फायरिंग' हथियार हो सकता है, क्योंकि मौके पर कारतूस के खाली खोल मिले हैं।

अमेरिकी सेना के जब्त किए गए ईरानी कार्गो जहाज से जुड़ा है चीन का संबंध

वॉशिंगटन। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ओमान की खाड़ी में अमेरिकी बलों द्वारा जब्त किया गया ईरानी कार्गो जहाज उन जहाजों के बेड़े का हिस्सा था, जिसका संबंध चीनी बंदरगाहों और संदिग्ध आपूर्ति मार्गों से था।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक एमवी टौस्का नामक ईरानी झंडे वाला कंटेनर जहाज, उन जहाजों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जो अक्सर चीन जाते हैं और जिन पर संभावित सैन्य उपयोग वाली सामग्रियों के परिवहन का आरोप रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस जहाज को अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश के बाद रोका गया और बाद में चेतावनी के तौर पर चलाई गई गोलियों से इसका इंजन निष्क्रिय करने के बाद अमेरिकी बलों ने उस पर चढ़ाई की।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा उद्धृत शिपिंग डेटा के अनुसार जब्त किए जाने से पहले के हफ्तों में यह जहाज दो बार दक्षिणी चीन के झुहाई बंदरगाह पर गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि टौस्का एक प्रतिबंधित ईरानी कंपनी द्वारा नियंत्रित है, जिस पर तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए सामान ढोने का आरोप है।अमेरिकी अधिकारियों ने यह खुलासा नहीं किया है कि जहाज में क्या सामान था। विश्लेषकों का कहना है कि सक्रिय नाकेबंदी को पार करने की कोशिश यह संकेत देती है कि माल महत्वपूर्ण हो सकता है पूर्व अमेरिकी नौसेना अधिकारी चार्ली ब्राउन ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा, 'नाकेबंदी तोड़ने का जोखिम उठाना उनके लिए फायदेमंद लग रहा होगा लेकिन उन्होंने गलत निर्णय लिया।' फॉक्स न्यूज डिजिटल की अलग रिपोर्ट में कहा गया कि यह जहाज ईरान की ओर बढ़ने से पहले दक्षिण-पूर्व एशिया और चीनी बंदरगाहों से होकर गुजरा था। रिपोर्ट में उद्धृत समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि कार्गो 'ड्यूल-यूज़' हो सकता है, यानी इसका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, जहाज को ईरानी जलक्षेत्र के पास होर्मुज जलडमरूमध्य के करीब रोका गया था। इससे पहले यह मलेशिया के पोर्ट क्लैंग में रुका था। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मार्ग अक्सर माल की उत्पत्ति को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया के जलक्षेत्रों में जहाज-से-जहाज ट्रांसफर आम हैं, जिससे शिपमेंट को ट्रैक करना कठिन हो जाता है।

अमेरिका ने उत्तर कोरिया से जुड़ी तकनीक के मामले में सियोल संग खुफिया जानकारी साझा करने पर लगाया आंशिक प्रतिबंध

सियोल। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के उपग्रहों के ज़रिए उत्तर कोरिया से जुड़ी तकनीक के बारे में जुटाई गई खुफिया जानकारी तक पहुंच को आंशिक रूप से सीमित कर दिया है। यह कदम एक विवाद के बाद उठाया गया है, जो एकीकरण मंत्री द्वारा उत्तर कोरिया की परमाणु सुविधा से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक किए जाने के बाद खड़ा हुआ था।

एक सूत्र के अनुसार, चूंकि सहयोगी देश आमतौर पर उत्तर कोरिया की निगरानी से जुड़ी जानकारी जैसे कि मिसाइल लॉन्च गतिविधियां आपस में साझा करते रहे हैं, इसलिए दक्षिण कोरियाई सेना को अपनी तत्परता बनाए रखने में कोई समस्या नहीं है।

वॉशिंगटन ने यह कदम तब उठाया, जब पिछले महीने संसद के एक सत्र के दौरान एकीकरण (यूनिफिकेशन) मंत्री चुंग डोंग-यंग ने उत्तर कोरिया के कुसोंग क्षेत्र का जिक्र करते हुए बताया था कि यह उन जगहों में से एक है, जहां देश की यूरेनियम संवर्धन सुविधा मौजूद है। उत्तर कोरिया से जुड़ी जानकारी का इस तरह सार्वजनिक रूप से खुलासा किया जाना एक दुर्लभ घटना थी। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा, 'यह सच है कि इस महीने की शुरुआत से ही अमेरिका ने उपग्रहों के ज़रिए जुटाई गई उत्तर कोरियाई खुफिया जानकारी के कुछ हिस्सों को साझा करने पर रोक लगा दी है। खुफिया जानकारी साझा करने पर लगाई गई यह रोक उत्तर कोरिया की तकनीक के कुछ हिस्सों से जुड़ी जानकारी से संबंधित है।' योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने प्रतिबंधित जानकारी के बारे में कोई विवरण नहीं दिया लेकिन माना जा रहा है कि यह जानकारी उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों से संबंधित है। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका के इस कदम से दक्षिण कोरियाई सेना की तत्परता पर कोई असर नहीं पड़ा है। सहयोगी देशों के बीच सैन्य गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान 'पहले की तरह ही' जारी है। मंत्री चुंग ने सांसदों को बताया था कि उत्तर कोरिया, योंगब्योन और कांगसोन में पहले से रिपोर्ट की गई जगहों के अलावा, उत्तर-पश्चिमी इलाके कुसोंग में भी यूरेनियम संवर्धन की एक और सुविधा चला रहा है। खबरों के मुताबिक, अमेरिका ने चुंग द्वारा इस जानकारी को सार्वजनिक किए जाने पर आपत्ति जताई है। उसका मानना है कि यह जानकारी वाशिंगटन द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी पर आधारित थी। एकीकरण मंत्रालय ने पिछले हफ़्ते कहा था कि चुंग ने ये टिप्पणियां 'सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी' के आधार पर की थीं। सोमवार को चुंग ने उन आरोपों पर खेद व्यक्त किया कि उनकी टिप्पणियों से जानकारी लीक हुई है। उन्होंने कहा कि कुसोंग का जिक्र करने का उनका मकसद दक्षिण कोरिया की उत्तर कोरिया नीति को स्पष्ट करना था।

सीडीएस अनिल चौहान की इंग्लैंड यात्रा, युद्धों के बदलते स्वरूप पर की चर्चा

नई दिल्ली। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यूके यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को दिशा देने वाली उच्चस्तरीय बैठकों व कार्यक्रमों में शिरकत की है।

इस दौरान उन्होंने यूके के रक्षा राज्य मंत्री ल्यूक पोलार्ड से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में आधुनिक युद्धों के बदलते स्वरूप, आधुनिक सैन्य चुनौतियों और सैन्य-से-सैन्य सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। सीडीएस ने यहां इंडो-पैसिफिक मामलों की राज्य मंत्री सीमा मल्होत्रा के साथ भी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता की। ह्वाइस दौरान भारत-यूके साझेदारी, रक्षा औद्योगिक रोडमैप और प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा से जुड़े सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। खासतौर पर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए दोनों पक्षों ने समन्वय बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठकों में साइबर, इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही सूचना सुरक्षा, इंफॉर्मेशन रेजिलिएंस और विशेष प्रशिक्षण आदान-प्रदान को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई। दोनों देशों ने भविष्य के लिए तैयार, मजबूत और सक्षम सशस्त्रबलों के निर्माण के साझा संकल्प को दोहराया है।

इन महत्वपूर्ण मुलाकातों से पहले सीडीएस अनिल चौहान ने यूके में एक उच्चस्तरीय राउंडटेबल सम्मेलन का नेतृत्व भी किया। इसमें कई प्रमुख अधिकारी, थिंक टैंक्स और विशेषज्ञों शामिल हुए।

अमेरिका ने ईरान का जहाज जब्त किया, तेहरान ने जवाबी कार्रवाई का लिया

वॉशिंगटन। अमेरिका ने अरब सागर में ईरान के ध्वज वाले मालवाहक जहाज पर गोलीबारी करने के बाद उसे जब्त कर लिया है। तेहरान ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे 'सशस्त्र समुद्री डकैती' करार दिया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। फिर से तनाव और बढ़ गया है।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के अनुसार, अमेरिकी नेवी ने ईरानी झंडे वाले जहाज एम/वी तासिका पर तब गोलीबारी की, जब उसने ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की। सेंटकॉम की ओर से बताया गया कि अमेरिकी सेना ने कार्रवाई करने से पहले, छह घंटे तक चले गतिरोध के दौरान बार-बार चेतावनी दी। कमांड ने कहा कि अमेरिकी सेना ने कई बार चेतावनी दी और ईरानी झंडे वाले जहाज को सूचित किया कि वह अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा है। जब जहाज के चालक दल ने आदेश का पालन नहीं किया, तो एक अमेरिकी गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया, जिससे उसका प्रोपल्शन सिस्टम (आगे बढ़ने का तंत्र) निष्क्रिय हो गया। यह ऑपरेशन इस महीने की शुरुआत में वाशिंगटन की ओर से ईरानी समुद्री गतिविधियों पर नाकाबंदी लगाए जाने के बाद से, बल प्रयोग का पहला ज्ञात मामला है; इसने होर्मुज जलडमरूमध्य पर केंद्रित टकराव में तनाव को काफी बढ़ा दिया है। ईरानी अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वाशिंगटन पर आक्रामकता का आरोप लगाया।

वेनेजुएला ने अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ राष्ट्रीय रैली निकालकर किया प्रदर्शन

काराकास। वेनेजुएला में अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी लामबंदी जारी है, जिसमें नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने राजनीतिक और सामाजिक एकता का आह्वान करते हुए एक रैली का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हमें प्रतिबंधों को खत्म करना होगा।

जॉर्ज रोड्रिगेज ने सैन फेलिक्स के सेरो एल गैलो में कहा कि इस अभियान का मकसद आम सहमति बनाना और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए दबाव डालना है। उन्होंने वेनेज़ुएला के लोगों से अपील की कि वे अपने मतभेद भुलाकर साझा हितों पर ध्यान दें। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह लामबंदी 19 अप्रैल को कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की ओर से शुरू की गई एक राष्ट्रीय रैली का हिस्सा है, जिसके तहत जुलिया, ताचिरा और अमेजोनस सहित कई राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जुलिया राज्य में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में, डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि वेनेज़ुएला को अमेरिका के प्रतिबंधों से पार पाना होगा; उन्होंने आगे कहा कि लगभग एक दशक से चले आ रहे आर्थिक प्रतिबंधों के दौरान पैदा हुए लाखों बच्चों को बुनियादी सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ा है।

इस राष्ट्रव्यापी अभियान में पूरे देश भर में मार्च और सार्वजनिक कार्यक्रम शामिल हैं, और इसका समापन एक मई को काराकास में होना निर्धारित है। पिछले महीने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेज़ुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। अमेरिकी ट्रेजरी के 'ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल' ने कहा कि रोड्रिगेज को उसकी प्रतिबंध सूची से हटा दिया गया है, हालाँकि उसने इस फैसले के बारे में और कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने इस अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया था।

संकुचित मानसिकता के चलते विपक्ष महिला आरक्षण बिल में रोड़े अटका रहा : सीएम योगी

लखनऊ। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक विपक्ष द्वारा खारिज किए जाने के विरोध में भाजपा की और से लखनऊ में 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा' निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ भाजपा कार्यकर्ता और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास से निकलकर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ विधानसभा तक पैदल पहुंचे। करीब 1.75 किलोमीटर की इस पदयात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। विधानसभा के बाहर सड़क पर बने मंच से पदयात्रा में शामिल हुए लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

मुख्यमंत्री ने कहा, आज बहनों के नेतृत्व में यह आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जन-विरोधी आचरण के कारण आज देश और प्रदेश की महिलाओं में भारी गुस्सा है। मोदी सरकार महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहती है लेकिन ये दल अपनी संकुचित मानसिकता के कारण रोड़े अटका रहे हैं।

सीएम योगी ने कहा, सपा-कांग्रेस और टीएमसी से महिलाएं नाराज हैं। देशभर में आक्रोश रैली निकल रही है। विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में केवल चार जाति महिला, गरीब, युवा और किसान है। इसमें सबसे पहली जाति महिला है। प्रधानमंत्री चाहते थे कि 2029 में ही महिला आरक्षण लागू हो जाए। इसके बाद भी विपक्ष ने महिला विरोधी काम किया है। आज की इस आक्रोश रैली में बहनें शामिल हुई हैं। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं के लिए योजनाएं चला रही है। उसी तरह डबल इंजन की सरकार में भी चलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, मैं उन सभी बहनों को तहे दिल से बधाई देता हूं, जिन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और आपको भरोसा दिलाता हूं कि राज्य का हर व्यक्ति आधी आबादी की उनके जायज़ मांग के समर्थन में उनके साथ खड़ा है। जन आक्रोश महिला पदयात्रा में शामिल उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जिन पार्टियों को महिलाओं के वोट नहीं मिलेंगे, वे विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे।

मणिपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.2 थी तीव्रता

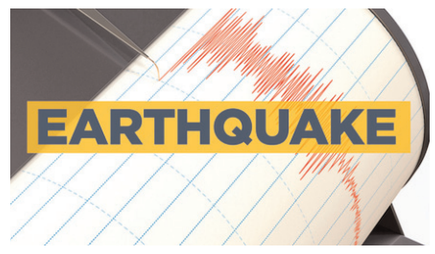

गांधीनगर। म्यांमार-भारत सीमा क्षेत्र में मंगलवार सुबह 5:59 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.2 रही। गांधीनगर स्थित भूकंपीय अनुसंधान संस्थान ने पुष्टि करते हुए बताया कि भूकंप की गहराई 84 किलोमीटर थी।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) ने जानकारी दी कि मणिपुर में मंगलवार सुबह 5.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। मणिपुर के साथ ही नगालैंड, असम और मेघालय तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, इसका केंद्र कामजोंग में स्थित था।

इससे पहले 18 अप्रैल को कश्मीर की घाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कश्मीर घाटी में 18 अप्रैल को रिक्टर पैमाने पर 5.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में था। घरों में पंखे सहित अन्य वस्तुएं हिलती हुई देख लोग घरों से निकल आए थे, लेकिन भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं थी।

आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने बताया कि 18 अप्रैल सुबह 8:24 बजे रिक्टर पैमाने पर 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र पृथ्वी के 190 किलोमीटर अंदर था। भूकंप विज्ञान के अनुसार, कश्मीर घाटी भूकंप की आशंका वाले क्षेत्र में स्थित है।

14 अप्रैल को भी जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, हालांकि दोनों जगहों पर कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई थी। जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, 14 अप्रैल की सुबह 4.55 बजे डोडा जिले की भदेरवाह घाटी और उसके आसपास के इलाकों में रिक्टर स्केल पर 2.9 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी 14 अप्रैल की सुबह 7:07 बजे पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर 3.4 की तीव्रता दर्ज की गई थी। सूचना पर जिला प्रशासन सतर्क हो गया था और भूकंप केंद्र पर पहुंचकर निरीक्षण किया था।

संक्षिप्त खबर

कदावुल मंदिर: भारत से 7 हजार मील दूर घने जंगलों में अनोखे रूप में विराजे हैं भगवान शिव; नटराज अवतार को समर्पित है मंदिर

नई दिल्ली। देशभर में भगवान शिव को समर्पित मंदिर हैं, जिनका अपना-अपना इतिहास है। देश में बारह ज्योतिर्लिंगों की मान्यता बहुत है, जिन्हें स्वयं भगवान शिव का जीवांत और चमत्कारी रूप माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की सीमा के पार भी ऐसा शिव मंदिर मौजूद है, जहां खुद भोलेबाबा जंगल की रक्षा करते हैं। यह मंदिर भारत से सात हजार मील से अधिक दूरी पर अमेरिका के हवाई राज्य के काउई द्वीप के जंगलों में स्थापित है। काउई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई राज्य का सबसे पुराना और चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, जहाँ के घने जंगलों के भीतर कदावुल मंदिर स्थापित है। माना जाता है कि मंदिर के आस-पास एक तेज ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, जो वहां दर्शन करने वाले भक्तों को महसूस होता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह ऊर्जा भगवान शिव की है, जो हमेशा मंदिर के भीतर निवास करती है और शिव भक्तों को महसूस होती है।

कदावुल मंदिर आस्था के साथ-साथ खूबसूरती का भी प्रतीक है। मंदिर के भीतर बहुत खूबसूरत पेड़-पौधे हैं, और भगवान शिव के अलावा मंदिर के भीतर मां पार्वती, नंदी महाराज, मुरुगन, और गणेष भगवान की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं। मंदिर के भीतर पानी का एक बड़ा कुंड भी है, जिसमें निरंतर पानी भरा रहता है। मंदिर के बनाव में श्री लंकाई शैली देखने को मिलती है। मंदिर के शंभों पर बने चित्र भारतीय परंपरा से बिल्कुल अलग हैं।

बात अगर मंदिर के गर्भगृह की करें तो मंदिर के भीतर 700 पाउंड वजनी और 3 फुट के स्वयंभू स्फटिक के शिवलिंग मौजूद हैं और एक विशाल भगवान शिव नटराज के रूप की प्रतिमा भी विराजमान हैं। आमतौर पर मंदिर में पत्थर के बने शिवलिंग की पूजने की प्रथा सदियों से चली आई लेकिन काउई द्वीप पर बने इस मंदिर में स्फटिक के पारदर्शी शिवलिंग की पूजा रोजाना की जाती है।

इसके साथ ही गर्भगृह के सामने लावा चट्टान और रेडवुड की लकड़ी से बना एक मंडप है, जिसमें 32,000 पाउंड वजन की एक ही पत्थर से तराशी गई नंदी की प्रतिमा स्थापित है। बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना सतगुरु शिवाय सुब्रमण्यस्वामी ने 1973 में की थी। यह मंदिर भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है।

ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंदिर में दर्शन का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक रहता है। 12 बजे के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन करने की मनाही है।

पंजाब के विकास के लिए सीएम भगवंत मान ने नीदरलैंड में तलाशीं साझेदारी की संभावनाएं

चंडीगढ़। नीदरलैंड के दौरे पर गए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ओलंपियन और डच हॉकी के दिग्गज फ्लोरिस जान बोवेलैंडर से मुलाकात की।

भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया कि आज नीदरलैंड्स में ओलंपियन और डच हॉकी के दिग्गज फ्लोरिस जान बोवेलैंडर से मिलकर बहुत खुशी हुई। खेल जगत में उनके योगदान और असाधारण कौशल की ख्याति पूरे विश्व में है।

मान ने लिखा कि उनकी शानदार यात्रा और अनुभव हमारे युवा खिलाड़ियों को बहुत प्रेरित करेंगे। हमने फ्लोरिस जान बोवेलैंडर को पंजाब आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। वे हमारे खिलाड़ियों से मिलेंगे और आगामी एशिया हॉकी चैंपियनशिप से पहले उनका उत्साह बढ़ाएंगे। पंजाब सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और हॉकी के स्वर्णिम युग को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भगवाल मान ने 20 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि नीदरलैंड्स के इंडिया हाउस में भारत के राजदूत श्री कुमार तुहिन से मुलाकात हुई। हमने कृषि, बागवानी, उद्योग, शिक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पंजाब के साथ संभावित साझेदारियों (टाई-अप्स) को तलाशने और उन्हें मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की। हमने आधुनिक तकनीकों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के माध्यम से पंजाब के समग्र विकास के लिए नए रास्ते भी तलाशे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 20 अप्रैल को नीदरलैंड्स में वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर का दौरा किया था। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा था कि नीदरलैंड्स में वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर का आज का दौरा बेहद सफल और उपयोगी रहा। हमने बागवानी की उन्नत तकनीकों, ग्रीनहाउस खेती और कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने के तरीकों का गहराई से अध्ययन किया। दुनिया के अग्रणी देशों की तरह हम भी पंजाब की कृषि को अगले स्तर तक ले जाने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी स्थापित करेंगे।

उन्होंने लिखा था कि हमारा लक्ष्य इस वैश्विक तकनीक को पंजाब तक लाना है, ताकि हम अपने मेहनती किसानों का एक अधिक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित कर सकें।

टीएमसी ने चुनाव आयोग से उत्तरपारा से भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ की शिकायत

हुगली। टीएमसी ने हुगली जिले की उत्तरपारा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिपांजन चक्रवर्ती के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। टीएमसी का दावा है कि भाजपा कुछ दिन पहले शुरू किए गए 'मातृ शक्ति भरोसा कार्ड' के जरिए मतदाताओं को रिश्वत देने की कोशिश कर रही है।

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पश्चिम बंगाल, डीईओ हुगली और सामान्य पर्यवेक्षक को संबोधित करते हुए टीएमसी ने पत्र लिखकर शिकायत की है। पत्र में टीएमसी ने लिखा है, 'हमें यह जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 185 उत्तरपारा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए दिपांजन चक्रवर्ती और उनके एजेंट व समर्थक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को एक फॉर्म भरवाकर, जिसका नाम 'मातृशक्ति भोष कार्ड' है, उन्हें 3000 मासिक भत्ता देने का वादा कर रहे हैं। मतदाताओं को रिश्वत देने की यह भ्रष्ट प्रथा भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवार द्वारा मुख्य रूप से उत्तरपारा निर्वाचन क्षेत्र के पंचायत क्षेत्रों में अपनाई गई है।

टीएमसी ने आगे लिखा है, 'मतदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी इस वादे के साथ एकत्र करना कि सत्ता में आने पर पार्टी उन्हें 3000 मासिक भत्ता देगी, अवैध, अनैतिक और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। केवल इसी कृत्य के लिए भाजपा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जानी चाहिए और उसके खिलाफ उचित आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए।'

इसके पहले 17 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर गंभीर आरोप लगाए था। पत्र में आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग द्वारा जारी 'फोर्स डिप्लॉयमेंट इन इलेक्शंस मैनुअल, 2023'', जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 का उल्लंघन किया गया है। फेसबुक पर प्रसारित एक वीडियो के आधार पर यह शिकायत की गई थी। वीडियो में कुछ नागरिक यह दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवान कथित तौर पर भाजपा उम्मीदवारों के साथ घूम रहे थे, भाजपा के पर्चे बांट रहे थे और मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे थे।'' पत्र में कहा गया था कि यह व्यवहार कथित तौर पर आपराधिक धमकी और चुनावी प्रक्रिया में अनुचित प्रभाव (धारा 174) के तहत अपराध है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि इस तरह की गतिविधियां मतदाताओं में डर का माहौल पैदा करती हैं और स्वतंत्र मतदान के अधिकार को प्रभावित करती हैं।

रांची में दिनदहाड़े कारोबारी को मारी गोली, सांसद संजय सेठ ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

रांची। झारखंड की राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मंगलवार सुबह पंडरा ओपी क्षेत्र के ओटीसी मैदान के समीप अपराधियों ने जमीन कारोबारी भार्गव सिंह को सरेराह गोली मार दी। पेट में गोली लगने से भार्गव सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

अस्पताल में प्राथमिक बयान के दौरान घायल भार्गव सिंह ने विजय टेटे नामक व्यक्ति पर गोली मारने का आरोप लगाया है। भार्गव के अनुसार, रातू स्थित एक जमीन को लेकर विजय के साथ उनका विवाद चल रहा था और विजय ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। आरोपी विजय टेटे मूल रूप से कांके के गांधीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए।

घटना के एक घंटे बाद पुलिस ने इस हमले की साजिश के आरोप में विजय टेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शूटरों की तलाश जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ सिटी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भार्गव सिंह की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल पारस अस्पताल रेफर कराया। सांसद के निर्देश पर पुलिस ने शहर में 'ग्रीन कॉरिडोर' बनाकर घायल को पारस अस्पताल पहुंचाया, जहां विशेषज्ञों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है।

घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे सांसद संजय सेठ ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, रांची में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वे सरेआम गोली मारकर पैदल ही निकल जा रहे हैं। यह स्थिति 90 के दशक के जंगलराज की याद दिलाती है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है।'

'भारत भूलता नहीं है...', पहलगाम हमले की बरसी से पहले बोली भारतीय सेना

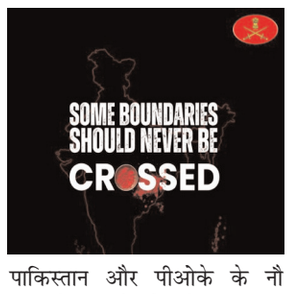

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के एक साल पूरे होने से एक दिन पहले भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जब मानवता की सीमाएं पार की जाती हैं, तो प्रतिक्रिया निर्णायक होती है। न्याय मिलता है। भारत एकजुट है।

भारतीय सेना ने कहा कि कुछ सीमाएं कभी पार नहीं करनी चाहिए, भारत भूलता नहीं है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए करारा जवाब दिया था। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान और पीओके के नौ आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था।

भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' से पाकिस्तान में टॉप-5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मुदस्सर खादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल, हाफिज मुहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ घोसी साहब, खालिद उर्फ अबू अक्शा, मोहम्मद हसन खान को ढेर कर दिया था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन घाटी में घूमने आए सैलानियों पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। पहलगाम आतंकी हमले से देशभर में आक्रोश फैल गया था। आतंकियों ने लोगों से नाम और धर्म पूछकर महिलाओं और बच्चों के सामने गोली मारी थी।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया।

नोएडा : हीट वेव का बढ़ता असर, स्कूलों में बच्चों को ग्राउंड जाने पर पाबंदी

नोएडा। नोएडा में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, तापमान में 21 अप्रैल से ही लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सुबह एवं शाम की आर्द्रता क्रमशः 37 और 20 प्रतिशत रही। इस दिन सतही तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान था, मगर असली चुनौती 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। मौसम विभाग ने 22 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम 22 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं, आर्द्रता का स्तर 45 से 20 प्रतिशत के बीच रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दिन हीट वेव रहेगी, खासकर दोपहर और शाम के समय हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। 23 अप्रैल को स्थिति और गंभीर हो जाएगी। अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आर्द्रता 45/20 प्रतिशत ही रहेगी, लेकिन दोपहर व शाम को हीट वेब का अलर्ट जारी रहेगा। 24 अप्रैल को भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री व न्यूनतम 24 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। आर्द्रता 45 से 20 प्रतिशत ही रहेगी और दोपहर-शाम हीट वेव जारी रहेगी। 25 अप्रैल को राहत के कुछ आसार हैं, जब अधिकतम तापमान 43 व न्यूनतम 25 डिग्री रह सकता है। आर्द्रता बढ़कर 50/25 प्रतिशत हो जाएगी और आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन कोई गंभीर चेतावनी नहीं होगी। 26 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41 व न्यूनतम 25 डिग्री तथा आर्द्रता 55/25 प्रतिशत रहेगी, मगर आसमान आंशिक बादलों वाला रहेगा। हीट वेव के इस गंभीर प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में बच्चों को खेल के समय ग्राउंड या बाहर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

नासा के हबल टेलीस्कोप ने कैद की ट्राइफिड नेबुला की शानदार तस्वीर, दिखाई 5 हजार प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड की झलक

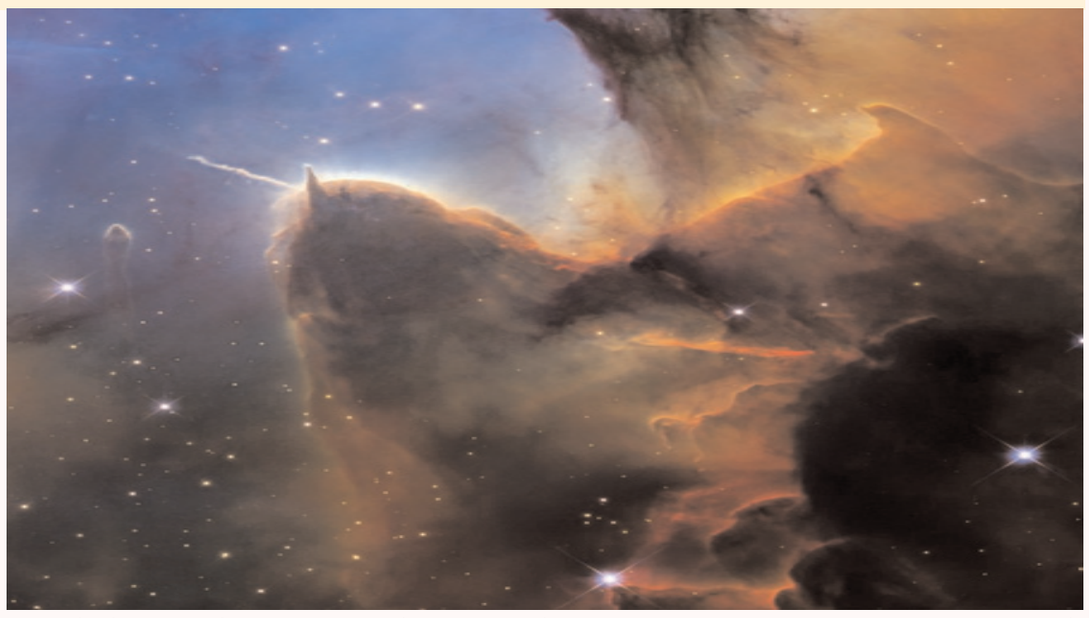

नई दिल्ली । अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने तारों के निर्माण वाले क्षेत्र ट्राइफिड नेबुला की एक आकर्षक नई तस्वीर जारी की है। यह तस्वीर हबल के लॉन्च की 36वीं वर्षगांठ (24 अप्रैल) के मौके पर सामने आई है। पृथ्वी से करीब 5 हजार प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह नेबुला तारों के बनने और गैस-धूल को आकार देने का अद्भुत नजारा पेश करता है।

यह नई तस्वीर न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि यह ब्रह्मांड में हो रही जटिल प्रक्रियाओं को समझने में भी अहम भूमिका निभाती है। हबल का यह मिशन लगातार वैज्ञानिकों को नई जानकारी दे रहा है और अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में मदद कर रहा है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, इस नेबुला में शक्तिशाली तारे अपने आसपास मौजूद गैस और धूल को प्रभावित करते हैं। उनकी तेज हवाएं और ऊर्जा इन बादलों को धकेलती है, जिससे नए तारों का निर्माण होता है। हबल द्वारा ली गई यह तस्वीर इस पूरी प्रक्रिया को बारीकी से दिखाती है, जिससे खगोलविदों को यह समझने में मदद मिलती है कि समय के साथ तारा निर्माण कैसे विकसित होता है।

इस तस्वीर में एक अनोखा दृश्य दिखाई देता है, जिसे वैज्ञानिक 'कॉस्मिक सी लेमन' जैसा रूप बताते हैं। यह संरचना गैस और धूल के बादलों से बनी है, जो देखने में किसी समुद्री जीव जैसी लगती है। इसके भीतर कई युवा तारे बन रहे हैं, जिनमें से कुछ अपने आसपास जेट के रूप में ऊर्जा छोड़ रहे हैं। ये जेट प्लाज्मा की धाराओं के रूप में बाहर निकलते हैं और आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं।

हबल ने पहले भी वर्ष 1997 में इस नेबुला का अवलोकन किया था। अब करीब तीन दशक बाद फिर से उसी क्षेत्र की तस्वीर लेकर वैज्ञानिकों को तुलना का अवसर मिला है। इससे यह पता चलता है कि इतने लंबे समय में इस क्षेत्र में क्या बदलाव आए हैं। नई तकनीक और उन्नत कैमरों की मदद से इस बार अधिक स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर सामने आई है।

तस्वीर में अलग-अलग रंग भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। नीले रंग वाले हिस्से अपेक्षाकृत साफ हैं, जहां बड़े तारों की पराबैंगनी रोशनी ने गैस को आयनित कर दिया है। वहीं गहरे भूरे और काले क्षेत्र घनी धूल को दर्शाते हैं, जहां अभी भी तारे बन रहे हैं और जो सामान्य रोशनी में दिखाई नहीं देते।

इस नेबुला में कई प्रोटोस्टार यानी नवजात तारे मौजूद हैं, जो अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं। कुछ स्थानों पर जेट और गैस की धाराएं यह संकेत देती हैं कि ये तारे अपने आसपास ऊर्जा छोड़ रहे हैं। इससे वैज्ञानिक यह समझ पाते हैं कि नए तारे अपने वातावरण के साथ किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं।

तस्वीर के एक हिस्से में घनी धूल के कारण लगभग अंधेरा दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां दिखने वाले कुछ तारे वास्तव में इस नेबुला का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब मौजूद हो सकते हैं। वहीं, कुछ चमकीले नारंगी रंग के तारे ऐसे हैं, जो पूरी तरह विकसित हो चुके हैं और उन्होंने अपने आसपास की धूल को साफ कर दिया है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले लाखों वर्षों में इस नेबुला की गैस और धूल धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी और यहां केवल तारे ही बचेंगे। हबल टेलीस्कोप की लंबी उम्र और उन्नत तकनीक की वजह से इस तरह के अवलोकन संभव हो पाए हैं।

भारत में हेल्थकेयर में एआई का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल, 85 प्रतिशत के साथ दुनिया में सबसे आगे: रिपोर्ट

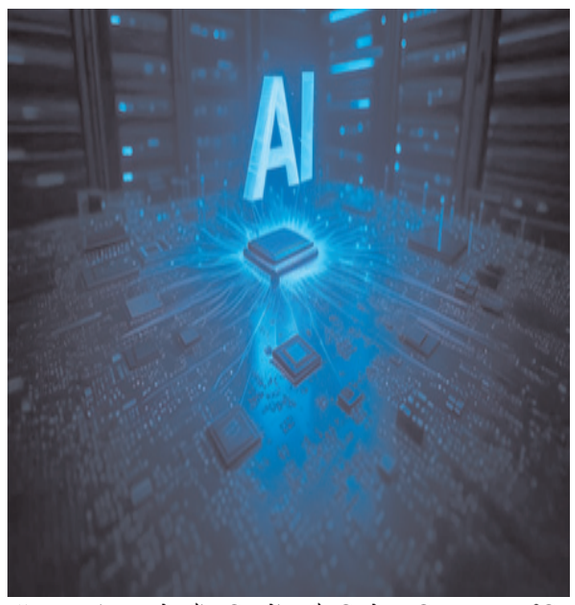

मुंबई । भारत पर्सनल हेल्थ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अपनाने के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। एक नई रिपोर्ट में मंगलवार को कहा गया कि भारत में 85 प्रतिशत लोग पहले से ही एआई-आधारित टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो विकसित देशों से काफी ज्यादा है।

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, (जिसका शीर्षक है 'उपभोक्ता एआई-सक्षम स्वास्थ्य सेवा के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य प्रणाली को भी तैयार रहने की आवश्यकता है') भारतीय उपयोगकर्ता जनरेटिव एआई को दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कहीं तेजी से अपना रहे हैं।

यह रिपोर्ट 15 देशों के 13,000 से ज्यादा लोगों पर किए गए सर्वे पर आधारित है, जिसमें बताया गया कि भारत का एआई अपनाने का स्तर अमेरिका (50 प्रतिशत), ब्रिटेन (43 प्रतिशत) और जापान (34 प्रतिशत) से काफी ज्यादा है।

दुनिया भर में करीब 60 प्रतिशत लोग हेल्थ से जुड़े कामों के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारत इस मामले में सबसे आगे है। यह दिखाता है कि देश में डिजिटल हेल्थ टूल्स को लेकर लोगों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, मरीज अब इलाज के तरीके को लेकर नई सोच अपना रहे हैं। ज्यादातर लोग ऐसा मॉडल पसंद करते हैं, जिसमें डॉक्टर और एआई मिलकर काम करें, न कि एआई डॉक्टरों की जगह ले।

यह तरीका खासकर टेस्ट रिपोर्ट समझने और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों (क्रॉनिक कंडीशन) को मैनेज करने में ज्यादा उपयोगी माना जा रहा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि युवा पीढ़ी इस बदलाव को तेजी से आगे बढ़ा रही है। करीब 78 प्रतिशत जेनरेशन जेड और 71 प्रतिशत मिलेनियल्स हेल्थ से जुड़े कामों के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।

फिलहाल हेल्थकेयर में एआई का इस्तेमाल ज्यादा तर चैटबॉट्स और वियरेबल डिवाइस तक सीमित है, लेकिन लोगों की उम्मीदें तेजी से बढ़ रही हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'अभी 33 प्रतिशत लोग चैटबॉट्स और 19 प्रतिशत लोग वियरेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब लोग ऐसे एडवांस 'एजेंटिक एआई' की उम्मीद कर रहे हैं जो खुद से अपॉइंटमेंट बुक कर सके, रेफरल मैनेज कर सके और दवाओं के बीच संभावित इंटरैक्शन की पहचान कर सके।

उपभोक्ता अब ऐसे स्मार्ट एआई सिस्टम चाहते हैं जो अपने आप कई जरूरी काम कर सकें और हेल्थकेयर को ज्यादा आसान और प्रभावी बना सकें।

देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ाने की केंद्र की बड़ी तैयारी, जल्द आ सकता है आईएसएम 2.0 : रिपोर्ट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में तेजी से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विस्तार के लिए मई तक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 'आईएसएम 2.0' लाने की तैयारी कर रही है। इसका प्रस्तावित परिव्यय एक लाख करोड़ रुपए से 1.2 लाख करोड़ रुपए के बीच रहने का अनुमान है।

एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक, आईएसएम 2.0 को लेकर मंत्रालयों के बीच बातचीत चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि आईएसएम 2.0 में प्रस्तावित परिव्यय पहले चरण से काफी अधिक होने का अनुमान है, जो कि पहले 76,000 करोड़ रुपए था।

सूत्रों ने आगे बताया कि आईएसएम 2.0 के तहत, सरकार का लक्ष्य कार्यक्रम के दायरे को चिप निर्माण और डिजाइन से आगे बढ़ाकर सेमीकंडक्टर उपकरण, कच्चे माल और अन्य महत्वपूर्ण इनपुट के लिए समर्थन को शामिल करना है, साथ ही पूर्ण-स्टैक बौद्धिक संपदा के निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला की लचीलता को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करना है। सरकार यह कदम ऐसे समय पर उठा रही है, जब वैश्विक अस्थिरता के कारण ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखलाओं में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहे हैं।

गैस आपूर्तिकर्ता, विशेष रसायन निर्माता, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और अन्य इकोसिस्टम के भागीदार जैसे सहायक खिलाड़ी इस संशोधित ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

दूसरे चरण की एक प्रमुख विशेषता संशोधित डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई 2.0) योजना है, जिसके तहत विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ देश के भीतर सेमीकंडक्टर रिसर्च और डेवलपमेंट में साझेदारी करने की अनुमति मिलने की संभावना है।

इस पहल से इनोवेशन को गति मिलने और आने वाले वर्षों में 50 तक फैबलेस सेमीकंडक्टर डिजाइन फर्मों के उदय को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

मार्च 2025 में भारत के पहले 'नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोडशो' में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा था कि घरेलू सेमीकंडक्टर मांग बाजार 2030 तक 110 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।

थायराइड और हार्मोन असंतुलन में कंचनार गुग्गुलु के फायदे

नई दिल्ली । सदियों से हमारे देश में जड़ी-बूटियों से रोगों का निदान किया जा रहा है। कुछ जड़ी-बूटियां ऐसी हैं, जो संजीवनी की तरह काम करती हैं और शरीर को रोग मुक्त करने में मदद करती हैं।

कंचनार गुग्गुलु भी आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण औषधियों में से एक है, जिसका इस्तेमाल शरीर की सूजन और गांठों को कम करने में होता आया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंचनार गुग्गुलु से थायराइड को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।

आयुर्वेद में कंचनार गुग्गुलु को मुख्य औषधि का दर्जा दिया गया है। यह शरीर में गांठों, पीसीओएस, गर्भाशय फाइब्रॉएड और ग्रंथियों की सूजन के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। यह शरीर में कफ और मेद धातु को भी संतुलित करने में मदद करती है लेकिन अगर थायराइड में इसे चिकित्सक की सलाह के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसके हैरान कर देने वाले फायदे देखने को मिलेंगे।

आयुर्वेद मानता है कि अगर शरीर में टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, तो शरीर में गांठ बनने की संभावना अधिक होती है और हॉर्मोन का असंतुलन भी होता है, जिससे गर्भाशय से जुड़े रोग और थायराइड की परेशानी शरीर में बनना शुरू हो जाती है। ऐसे में कंचनार गुग्गुलु का सेवन किया जाए, तो शरीर से टॉक्सिन आसानी से बाहर निकल जाते हैं और कफ और वात दोष भी संतुलित रहते हैं।

कंचनार में एंटी-इंफ्लेमेटरी और शरीर को डिटॉक्स करने वाले गुण होते हैं, और गुग्गुलु मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त बनाए रखने में मदद करता है। इससे शरीर का पूरा पाचन सिस्टम साफ होना शुरू कर देता है। बाजार में आसानी से कंचनार गुग्गुलु पाउडर और गोली के रूप में मिल जाते हैं, लेकिन सही मात्रा और सही बीमारी में सेवन के लिए चिकित्सक की सलाह जरूर लें। कंचनार गुग्गुलु के साथ जीवनशैली में बदलाव करना भी उतना ही जरूरी है। आहार में जंक फूड और मीठे का सेवन कम करें। रिफाइंड चीनी से बने उत्पाद पीसीओडी और थायराइड दोनों को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं। रोजाना सैर पर जएं और हल्का फुल्का वॉक करें। इसके साथ ही रात के समय हल्दी वाला दूध लेना न भलें। इससे थायराइड ग्रांथि से जुड़े हॉर्मोन संतुलित रहते हैं। सुबह की शुरुआत धनिए से करें।

बात-बात पर बढ़ जाता है बीपी? योग और सही डाइट से करें कंट्रोल

नई दिल्ली । आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खराब लाइफस्टाइल, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा या तनाव के कारण हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) की समस्या बढ़ने लगी है। कई बार इसके लक्षण साफ नजर भी नहीं आते, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। सही लाइफस्टाइल और कुछ आदतों में बदलाव कर इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपका वजन ज्यादा है या ज्यादा नमक खाते हैं, स्मोकिंग या शराब का सेवन करते हैं या फिर आपकी दिनचर्या में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो बीपी बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा लगातार तनाव में रहना भी बड़ा कारण है। कई लोगों में यह समस्या परिवार से भी जुड़ी होती है।

अक्सर हाई बीपी के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं, जैसे सुबह-सुबह सिरदर्द, चक्कर आना, घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना या कभी-कभी नाक से खून आना। अगर ये लक्षण बार-बार दिखें, तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत बीपी चेक कराएं। इसमें योग और सही डाइट आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं। योग सिर्फ शरीर ही नहीं, मन को भी शांत करता है। रोजाना 20-30 मिनट योग करने से तनाव कम होता है और बीपी भी नियंत्रित रहता है। कुछ आसान योगासन जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, शशांकासन और शवासन बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। इसके साथ ही प्राणायाम जैसे अनुलोम-विलोम (नाड़ी शोधन), भ्रामरी और शीतली करने से मन शांत होता है ।

शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला नेचुरल ड्रिंक है लस्सी, जानें पीने का सही समय

नई दिल्ली । गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडक और ताजगी देने वाले कोल्ड ड्रिंक्स की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में लोग अक्सर सेहत से खिलवाड़ करते हुए डब्बा बंद आर्टिफिशियल पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, जो सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं। वहीं, लस्सी एक ऐसा पारंपरिक ड्रिंक है, जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि शरीर के तापमान को संतुलित रखने में भी मदद करती है। दही से तैयार होने वाला यह पेय भारत में लंबे समय से खानपान का अहम हिस्सा रहा है।

लस्सी एक ऐसा पेय है जो स्वाद और सेहत दोनों का बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है। अगर इसे सही समय पर और संतुलित मात्रा में पीया जाए, तो यह गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है। लस्सी को आमतौर पर दही को मथकर उसमें चीनी समेत अन्य स्वाद बढ़ाने वाली चीजें मिलाकर बनाया जाता है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इसका स्वाद और बनाने का तरीका भी बदल जाता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, लस्सी एक प्राकृतिक कूलिंग एनर्जी ड्रिंक है, जिसकी तासीर ठंडी होती है। यही कारण है कि गर्मियों में इसका सेवन शरीर को तुरंत राहत देता है और तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसके अलावा, लस्सी पाचन तंत्र को मजबूत करती है, शरीर को हाइड्रेट रखती है और तुरंत एनर्जी भी प्रदान करती है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है।

हालांकि, लस्सी पीने का सही समय जानना भी उतना ही जरूरी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इसका सेवन दिन में, खासकर दोपहर के समय करना सबसे अधिक फायदेमंद होता है।

शरीर का 'रिपेयर मैनेजर' जिंक: कमी से शरीर हो सकता है बेहद कमजोर

नई दिल्ली । आज के समय में विटामिन और प्रोटीन के बारे में सभी बात करते हैं और शरीर में उनके स्तर को ठीक बनाए रखने के लिए सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं।

विटामिन और प्रोटीन के अलावा हमारे शरीर में कई ऐसे खनिज और पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो साइलेंट तरीके से शरीर की ऊर्जा को बनाए रखते हैं, जैसे जिंक। जिंक को आयुर्वेद और विज्ञान दोनों में शरीर के लिए महत्वपूर्ण माना है; इसे शरीर का 'रिपेयर मैनेजर' माना जाता है, जो शरीर में हार्मोन संतुलन से लेकर एंजाइम्स को सक्रिय करने का काम करता है।

शरीर में छिपकर काम करने वाले जिंक की कमी से शरीर बेहद कमजोर हो जाता है। इसी कमी से थकान, बार-बार बुखार आना, घाव देर से भरना, भूख की कमी, बालों का तेजी से झड़ना और मानसिक रूप से बेवजह थकान होती है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बुरी तरीके से प्रभावित होती है क्योंकि जिंक हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य आधार है। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करता है और बाहरी संक्रमण से लड़ने की शक्ति देता है।

वहीं, बच्चों के विकास में भी जिंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जिंक बहुत आवश्यक है। यह हड्डियों को मजबूती देने से लेकर मस्तिष्क की कार्यक्षमता को मजबूत करता है। इसके साथ ही जिंक घावों का देरी से भरना, बार-बार सर्दी-जुकाम होना और भूख में कमी को भी ठीक करता है। यह त्वचा की कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जिंक अच्छी मात्रा में मांसाहारी खाने में मिलता है। यह अंडा, मछली, चिकन और झींगे में अच्छी मात्रा में मिल जाता है। वहीं, अगर आप शाकाहारी हैं तो केला, पालक, कद्दू के बीज, बादाम, अखरोट, तिल, ब्रोकली और दूध-दही में जिंक मिल जाता है। अब सवाल है कि कितना जिंक शरीर के लिए जरूरी है।

महाराष्ट्र पिकलबॉल एसोसिएशन के सहयोग के बिना 3 स्वर्ण पदक जीतना संभव नहीं था: अर्जुन और आदित्य सिंह

मुंबई । अर्जुन और आदित्य सिंह ने हाल ही में नेपल्स, फ्लोरिडा में हुई यूएस ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। महाराष्ट्र पिकलबॉल एसोसिएशन और इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन के सहयोग से, दोनों भाइयों ने वैश्विक पिकलबॉल मंच पर अपनी जगह पक्की कर ली है। दोनों इस खेल में भारत की श्रेष्ठ प्रतिभा हैं।

नए यूएस ओपन चैंपियन बने ये भाई अब महाराष्ट्र पिकलबॉल एसोसिएशन और आईपीए के अंतर्गत होने वाले महाराष्ट्र ओपन 2026 में हिस्सा लेंगे।

यूएस ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप 2026 के विजेता आदित्य ने कहा, 'अर्जुन और मैं बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। राहुल कनाल सर और महाराष्ट्र पिकलबॉल एसोसिएशन ने हम पर जो भरोसा दिखाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। यूएस ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप में भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक जीतना संभव नहीं था। हम भविष्य में भारत के लिए परिणाम लाने के उत्सुक हैं।

उन्होंने कहा, 'राहुल कनाल सर का खास जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने यह पक्का करने में कोई झिझक नहीं दिखाई कि हमारे पास वह सब कुछ है जो एक एथलीट को सबसे ऊंचे स्तर पर सफल होने के लिए चाहिए।

यूएस ओपन पिकलबॉल चैंपियनशिप में भारत की फाइनल गिनती 8 पदकों की रही, जिसमें कई श्रेणी में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल थे।

आदित्य और अर्जुन सिंह ने पुरुष डबल 5.0 श्रेणी और अंडर18 लड़कों की डबल्स श्रेणी में एक के बाद एक 2 स्वर्ण पदक जीते। दोनों इवेंट्स में दोनों भाइयों ने टॉप सीड और पसंदीदा खिलाड़ियों को हराया। यूएस ओपन में पुरुष एकल 5.0 इवेंट जीतकर अर्जुन सिंह ने भारत की गिनती में तीसरा गोल्ड मेडल जोड़ा था।

दोनों भाइयों ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि महाराष्ट्र ओपन तक भी हम अपने फॉर्म को जारी रखेंगे।

आईपीएल 2026: मलिंगा-हर्ष का चला जादू, एसआरएच ने डीसी को 47 रनों से रौंदा

हैदराबाद। आईपीएल 2026 के 31वें मुकाबले में मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) को 47 रनों से हराया। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एसआरएच से मिले 243 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 195 रन ही बना सकी। यह एसआरएच की इस सीजन की चौथी जीत है।

243 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पथुम निसांका सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि, इसके बाद केएल राहुल और नीतीश राणा ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों में 86 रनों की अहम साझेदारी निभाई। राहुल 23 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए, वहीं नीतीश ने अर्धशतक लगाते हुए 30 गेंदों में 57 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए।

डेविड मिलर को ईशान मलिंगा ने बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई। ट्रिस्टन स्टब्स अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे, और वह 16 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए। आशुतोष शर्मा भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके, और वह 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। समीर रिजवी 28 गेंदों में 41 रन बनाकर हर्ष दुबे का शिकार बने। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए। कप्तान अक्षर पटेल सिर्फ 2 रन ही बना सके, तो लुंगी एनगिडी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। एसआरएच की ओर से गेंदबाजी में ईशान मलिंगा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं, हर्ष दुबे ने 2 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट निकाले।

इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 242 रन बनाए। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने टीम को दमदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 8.5 ओवर में 97 रन जोड़े।

हेड 26 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए। ईशान किशन और अभिषेक ने इसके बाद दूसरे विकेट के लिए 35 गेंदों में 79 रनों की साझेदारी निभाई। ईशान 13 गेंदों में 25 रन बनाकर रनआउट हुए।

हालांकि, अभिषेक ने एक छोर से अपनी आतिशी बल्लेबाजी जारी रखी और अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक लगाया। अभिषेक ने 68 गेंदों का सामना करते हुए 135 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 10 छक्के लगाए। वहीं, हेनरिक क्लासेन 13 गेंदों में 37 रन बनाकर नाबाद रहे। अभिषेक-क्लासेन ने तीसरे विकेट के लिए 32 गेंदों में 66 रनों की अटूट साझेदारी निभाई। डीसी की ओर से गेंदबाजी में एकमात्र विकेट अक्षर पटेल को मिला।

आईसीसी टी20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा का जलवा, हरमनप्रीत को भी पहुंचा फायदा

दुबई। आईसीसी की ताजा महिला टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में शेफाली वर्मा ने दो पायदान की छलांग लगाई है। वहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 47 रनों की नाबाद पारी खेलने वाली भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर टॉप 10 में वापसी के करीब पहुंच गई हैं। टी20 रैंकिंग में यह बदलाव भारत और साउथ अफ्रीका अफ्रीका के बीच चल रही पांच मुकाबलों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बीच हुआ है, जिसमें दोनों टीमों की कई खिलाड़ियों को इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से शुरू होने वाले आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनके हालिया प्रदर्शन के लिए इनाम मिला है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में 38 गेंदों में 57 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद शेफाली वर्मा आईसीसी की बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर आ गई हैं। 2 टी20 मुकाबलों में शेफाली ने अब तक 156 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 91 रन बनाए हैं। स्मृति मंधाना चौथे स्थान पर भारत की सबसे ऊंची रैंकिंग वाली बल्लेबाज बनी हुई हैं।

भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी 2 पायदान का फायदा पहुंचा है। वह 11वें स्थान पर पहुंच गई हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में हरमनप्रीत ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और एक छक्के की मदद से 47 रनों की दमदार पारी खेली थी। साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 34 गेंदों पर खेली गई 54 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसके दम पर वह बल्लेबाजों की रैंकिंग में पांचवें स्थान पर बनी हुई हैं। एनेरी डर्कसेन 18 पायदान की छलांग लगाकर 33वें नंबर पर आ गई हैं, जबकि सुने लुस 8 पायदान ऊपर चढ़कर 35वें नंबर पर पहुंच गई हैं। गेंदबाजों की टी20 रैंकिंग में पाकिस्तान की गेंदबाज सादिया इकबाल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में दुनिया की नंबर एक गेंदबाज बनी हुई हैं।

पहले चीन के लिए खेला, अब कजाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियन फैंग बो

बीजिंग । चीन की मेंस टेबल टेनिस टीम के पूर्व सदस्य फैंग बो अब भविष्य की प्रतियोगिताओं में कजाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि, इसमें ओलंपिक खेल, वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप शामिल नहीं होंगे। फैंग ने सोमवार को इसका ऐलान किया।

फैंग ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'वीबो' पर लिखा, 'मैं अपनी वापसी की घोषणा करता हूं और कजाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करूंगा।

मैंने नोमैड टेबल टेनिस एकेडमी के साथ सहयोग स्थापित किया है। मैं जून से वर्ल्ड टेबल टेनिस के इवेंट्स में प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहा हूं। मेरे पास अभी भी चीनी नागरिकता है। मैं उन तीन बड़े टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा।

34 वर्षीय फैंग ने चीन को टीम वर्ल्ड कप 2015 और वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप 2016 जीतने में मदद की थी। 'सिन्हुआ' की रिपोर्ट के अनुसार, फैंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 के फाइनल में पहुंचे थे, जहां उन्हें अपने ही टीम के साथी मा लोंग से हार का सामना करना पड़ा था।

फैंग ने 2021 में चीनी टीम से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने अंत में कहा, 'टेबल टेनिस के प्रति मेरा प्यार ही वह कारण है, जिससे मैं वापस आया हूं। मैं एक बार फिर अपनी सीमाओं को चुनौती देना चाहता हूं।

'शेकहैंड ग्रिप' का इस्तेमाल करने वाले दाएं हाथ के इस 33 वर्षीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में जगह बनाई थी। उन्होंने इस सफर में दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जू शिन और मौजूदा चैंपियन झैंग जिके को हराया था।

साल 2017 में फैंग ने जर्मनी की पेट्रिसा सोल्जा के साथ जोड़ी बनाकर जर्मनी के डसेलडोर्फ में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फैंग ने एशियन चैंपियनशिप 2017 में भी डबल्स में सिल्वर और मिक्स्ड डबल्स में ब्रॉन्ज जीता था।

फ्रेंच ओपन से पहले पूरी तरह फिट होना है: कार्लोस अल्काराज

मैड्रिड । स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन 2026 से पहले फिटनेस संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं। कलाई की चोट से जूझ रहे अल्काराज ने स्वीकार किया है कि मेडिकल टेस्ट के बाद तय होगा कि वह अगले फ्रेंच ओपन में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं।

दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी को यह समस्या बार्सिलोना में अपने शुरुआती मुकाबले के दौरान हुई, जिसके बाद उन्हें बार्सिलोना ओपन और मैड्रिड ओपन जैसे बड़े टूर्नामेंट्स से हटना पड़ा। यह चोट ऐसे समय पर आई है जब अल्काराज शानदार फॉर्म में थे और रोलां गैरोस में दो बार के डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरने की तैयारी कर रहे थे।

अल्काराज ने कहा, 'मैं जल्दीबाजी नहीं, बल्कि थोड़ा इंतजार करके पूरी तरह फिट होकर लौटना पसंद करूंगा। मैं जल्दीबाजी कर अपनी स्थिति और खराब नहीं करना चाहता। लंबा करियर सामने है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। टेनिस जगत की निगाहें उनकी फिटनेस पर टिकी हैं। जैसे-जैसे रोलां गैरोस नजदीक आ रहा है, यह देखना दिलचस्प होगा कि अल्काराज जोखिम उठाते हैं या पूरी तरह फिट होकर वापसी का इंतजार करते हैं।

उनकी गैरमौजूदगी का असर एटीपी रैंकिंग पर भी पड़ा है। इटली के स्टार जानिक सिनर ने मोंटे कार्लो मास्टर्स के फाइनल में जीत हासिल कर दुनिया का नंबर 1 स्थान फिर से अपने नाम कर लिया। इससे रैंकिंग की प्रतिस्पर्धा और दिलचस्प हो गई है, खासकर क्ले-कोर्ट सीजन के अहम चरण में।

चोट के बावजूद, कोर्ट के बाहर अल्काराज के लिए खुशी की खबर भी आई। उन्हें मैड्रिड में आयोजित समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 चुना गया। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए उन्होंने साइक्लिंग स्टार तादेज पोगाकर, फुटबॉलर उस्मान डेम्बेले और पोल वॉल्ट चैंपियन आर्मंड डुप्लांटिस जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा।

अल्काराज ने अपने पिछले सीजन को याद करते हुए कहा कि दो ग्रैंड स्लैम जीतना और साल को नंबर 1 के रूप में खत्म करना उनके बचपन का सपना था। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और टीम को दिया, जिन्होंने मुश्किल समय में उनका साथ निभाया।

आईपीएल 2026: क्या डीसी पाथुम निसांका की जगह 26 साल के इस सलामी बल्लेबाज को मौका दे सकती है?

हैदराबाद । आईपीएल 2026 का 31वां मुकाबला मंगलवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बीच खेला जाएगा। डीसी के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी परेशानी का कारण रही है। हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली पृथ्वी शॉ को मौका दे सकती है।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए सीजन में पारी की शुरुआत केएल राहुल के साथ श्रीलंका के पथुम निसांका कर रहे हैं। पिछले 5 मैचों में निसांका एक भी बड़ी और विस्फोटक पारी खेलने में सफल नहीं रहे हैं। उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं है। निसांका 5 मैचों की 5 पारियों में 128 रन बना पाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 44 रहा है। उनकी असफलता से डीसी की शुरुआत तो खराब हो ही रही है, मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ रहा है।

हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मैच में डीसी पथुम निसांका की जगह पृथ्वी शॉ को मौका दे सकती है। शॉ को सीजन के पहले मैच का इंतजार है। 26 साल के शॉ एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं।

ओलंपिक 2028 पर हमारी नजर, लैक्रोस टीम 2026 एशियन गेम्स की तैयारी में: अनुदीप रेड्डी

नई दिल्ली । भारत के अनुदीप रेड्डी न सिर्फ ओलंपिक का सपना देख रहे हैं, बल्कि देश में लैक्रोस के विकास में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। नेशनल टीम 2026 एशियन गेम्स की तैयारी कर रही है। रेड्डी ने बताया कि वह एक ऐसा सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं जो कुछ ही सालों में भारत को लैक्रोस का पावरहाउस बना देगा।

कानून के विद्यार्थी और पहले हॉकी खिलाड़ी रहे रेड्डी, ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे वैश्विक मल्टी-स्पोर्ट इवेंट से जुड़े कम जाने-पहचाने खेलों की जानकारी लेने के क्रम में लैक्रोस के बारे में जान गए।

ओलंपिक्स डॉट कॉम को रेड्डी ने बताया, 'मैं एक दिन बोर हो रहा था और ऐसे नए खेल खोजने लगा जो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे मल्टी-स्पोर्ट इवेंट का हिस्सा हों। तभी मेरी नजर लैक्रोस पर पड़ी। ओलंपिक किसी भी एथलीट के लिए सबसे बड़ा स्टेज होता है। यह मेरे लिए इस खेल को अपनाने की मुख्य वजहों में से एक था।

रेड्डी तेजी से इस खेल में आगे बढ़े और कुछ ही महीनों में नेशनल सेटअप में जगह बना ली। सिर्फ तीन साल बाद, उन्होंने भारत को एशियन लैक्रोस गेम्स में ऐतिहासिक जीत दिलाई, जो देश में अभी भी अपने शुरुआती दौर में चल रहे एक खेल के लिए एक बड़ा मील का पत्थर था।

निजी उपलब्धियों से आगे देखते हुए, रेड्डी लैक्रोस को लंबे समय तक असर डालने वाले एक खेल के तौर पर देखते हैं।

उन्होंने कहा, 'अगर आप लैक्रोस जैसे उभरते हुए खेल में आते हैं, तो आप असल में शुरू से सिस्टम बना सकते हैं और निचले स्तर से खिलाड़ियों को ला सकते हैं। आप पहले से बने सिस्टम में आने की कोशिश करने की तुलना में बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें भारत असल में कुछ सालों में एक बड़ी शक्ति बन जाए।

रेड्डी ने कहा, 'यह सब नया है, खिलाड़ियों को कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं।

शाहरुख खान और राहुल तेवतिया पर जीटी का इतना भरोसा हैरान करने वाला: अभिनव मुकुंद

अहमदाबाद । गुजरात टाइटंस (जीटी) को सोमवार को अपने घरेलू मैदान नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ 99 रन से हार का सामना करना पड़ा। जीटी की हार के बाद टीम प्रबंधन द्वारा शाहरुख खान और राहुल तेवतिया पर किए जा रहे भरोसे को लेकर पूर्व क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने हैरानी जताई।

गुजरात टाइटंस की समस्या यह है कि अगर उनके शीर्ष के तीन बल्लेबाज (साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर) लंबी पारी खेलने में सफल नहीं रहे, तो मध्यक्रम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुंबई के खिलाफ मैच में यही हुआ। शीर्ष तीन बल्लेबाज सस्ते में निपट गए और मध्यक्रम भी नहीं चला। जीटी को 99 रन से हार का सामना करना पड़ा।

पूर्व क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने जीटी की इस समस्या का समाधान ईएसपीएनक्रिकइंफो के टाइमआउट शो में बताया।

उन्होंने कहा, जीटी के पास शायद वे समाधान हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। मुझे बहुत हैरानी है कि उन्होंने शाहरुख खान और राहुल तेवतिया पर इतना भरोसा किया। शायद उनका मानना ??है कि उन्होंने उनमें इतना निवेश किया है और यह एक ऐसा रोल है जिसे वे जरूरत पड़ने पर पूरा कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि उनके पास बेंच पर बैठे कुछ सबसे अच्छे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं। उनके पास निशांत सिंधु हैं, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स में एक साल खेला, उन्हें जीटी के लिए एक भी गेम नहीं मिला है। वह इंडिया ए का नियमित हिस्सा हैं।

अभिनव मुकुंद ने कहा, 'कुमार कुशाग्र ने अभी झारखंड के साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। ईशान किशन की सारी तारीफ हो रही है, लेकिन एक और लड़का था जो झारखंड के लिए बहुत रन बना रहा था। कुशाग्र ने 10 पारियों में 422 रन बनाए थे और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह झारखंड के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। कुशाग्र के पास अनुभव की कमी है लेकिन वह जीटी प्लेइंग इलेवन में चार नंबर पर बल्लेबाजी के लिए बेहतर विकल्प हैं।

स्वात्वधिकारी राइवल्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक सुजीत कुमार द्वारा साई प्रीटिंग प्रेस, डी-85, सेक्टर 6 नोएडा,गौतम बुध्द नगर पिन कोड -201301 उ.प्र. से मुद्रित और मकान संख्या एन-58 जगतराम पार्क के सामने, लक्ष्मी नगर पूर्व दिल्ली-110053 से प्रकाशित
समाचार संपादक : चन्द्रमणी साव (पीआरबी एक्ट के अनुसार समाचार पत्र चयन एवं संपादन के लिए उत्तरदायी। नोट किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र दिल्ली होगा) मोबाइल 9340573892 ई-मेल: vishwakesari2026@gmail.com,आर.एन.आई.नं. DLHIN/2015/61415